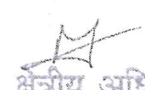


जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स जे. एस. डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता— 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट— 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा— 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉलर के साथ स्थापना, निकट गांव— हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील— नागौर एवं डेह, जिला— नागौर (राजस्थान) में स्थित है, में चूना पत्थर खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई जिला कलेक्टर नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राज कुमार भीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर में दिनांक 12/06/2025 को प्रातः 10:00 बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र "हिन्दुस्थान टाइम्स" एवं "दैनिक नवज्योति" में दिनांक 08/05/2025 को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स जे. एस. डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स जे.एम. इन्वायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स जे.एम. इन्वायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव—हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील— नागौर एवं डेह, जिला— नागौर (राजस्थान) में खनिज— चूना पत्थर खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका मौजूदा चूना पत्थर खनन परियोजना में प्रस्तावित विस्तार हेतु, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता— 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट— 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा— 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉल्लर के साथ स्थापना, निकट गांव— हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील— नागौर एवं डेह, जिला— नागौर (राजस्थान) में स्थित है, में चूना पत्थर खनन परियोजना है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनन परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री शिव भगवान, हेड, सीएसआर फण्ड, जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड ने कम्पनी द्वारा सीएसआर के अन्तर्गत किये गये कार्यों का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत किया गया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, इन्फ्रा, खेल प्रोत्साहन,


क्षेत्रीय अधिकारी
जनसुनवाई एवं पर्यावरण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

पानी, सामाजिक कार्यक्रम आदि पर किये जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी तथा कम्पनी द्वारा भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं के बारे में अवगत करवाया।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः आमंत्रित किया।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि इस प्रस्ताव में जल पर्यावरणीय प्रभाव एवं शमन में निकटवर्ती जल निकाय— छापर, जोंजोलाई, जाखोलाई, बामण्डा, पिनसरिया लिखा है। डेह के नौसर तालाब के लिए इसमें आपने क्या करना है अथवा क्या करेंगे? क्योंकि डेह का नौसर तालाब के बारे में बताया जाता है कि जब भदाना में ज्यादा बारिश होती है तो वहां का पानी भी डेह तालाब में आता है। यह आपके खनन के एरिया में ही है, यहां का पानी वहां तक आता है, इसके लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे? आपने इस लिस्ट में डेह के नौसर तालाब नाम दिया नहीं है, जिसका ताल लगभग यहां भदाना से शुरू होता है। इसके अन्दर आपने डेह का केवल बामण्डा एक ही तालाब लिखा है, जबकि डेह के अन्दर 10 छोटी-बड़ी नाड़ियां हैं, चौमासे के माह में सभी किसान एवं पशु उनका उपयोग करते हैं। प्रत्येक कांकड़ (गांव का बाहरी क्षेत्र) में छोटी-बड़ी नाड़ियां बनी हैं, उनको जलाशय के रूप में काम लिया जाता है। इस लिस्ट में उन सब का कोई वर्णन नहीं है, तो इन सब के बारे में थोड़ा स्पष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार को उक्त के संबंध में जानकारी देने हेतु कहा।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि इस पर्यावरण प्रभाव ईआईए रिपोर्ट के चेप्टर 3 में लेण्ड यूज में जितने भी जल निकाय आते हैं, जिनका विवरण दिया है, जिसमें सभी वाटर बॉडी कवर की गई है।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने पुनः कहा कि आप पढ़ कर बता दीजिये, इसमें क्या लिखा है, डेह के सारे तालाबों एवं नाड़ियों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, कि उनके लिए आप क्या करेंगे? पेज नम्बर 18 पर लिख रखा जल पर्यावरण प्रभाव शमन निकटवर्ती जल संकाय नाड़ियां— जिसमें पांच नाड़ियों के नाम—छापर, जांजोलाई, जाखोलाई, बामण्डा, जो डेह का ही एक छोटा सा, आबादी के अन्दर, जिसका पानी भी शायद पीने हेतु नहीं लेते हैं, तो भी उसका करवा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद! परन्तु जो काम में लिये जा रहे हैं, उनके लिए बताईयें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(रामपाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि उनके संरक्षण के उपाय किये जायेंगे, गहरीकरण, स्टोन पिचिंग आदि परियोजना क्षेत्र में प्रभावित गांवों में किये जायेंगे।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह द्वारा पुनः पूछा गया कि इसके सम्बन्ध में क्या आप लिखित में देंगे तथा यह सभी कार्य कब किये जायेंगे, जब आपकी कम्पनी काम शुरू कर देगी उसके बाद में, अथवा पहले आप गांवों के तालाब का काम करायेंगे। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, इस क्षेत्र के लोगों को तथा गांववालों को बता देता हूं कि अपने क्षेत्र में दिखनाद हवा चलती है, तो इस क्षेत्र में जो प्रदूषण होगा उसके लिए आपके द्वारा क्या किया जायेगा? हमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्रदूषण के लिए जवाब चाहिए। जिसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि जल संरक्षण के लिए जितने भी तालाब हैं, उसका रिन्यूवेशन एवं गहरीकरण के लिए लिखित में दे देंगे।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह द्वारा पुनः पूछा गया कि आप प्रदूषण के लिए क्या करोगे? तालाब की गहरीकरण, जितना गहरा है वो सफिसेंट है, ज्यादा गहराई में पानी ठहरेगा नहीं, तो गहराई नहीं चाहिए।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डवलप की जायेगी।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह द्वारा पुनः पूछा गया कि यह कैसे करेंगे, डिटेल में बताईयें कि कैसे करेंगे जिससे प्रदूषण नहीं होगा?

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि प्रदूषण तो खदान से जो ब्लास्टिंग होती है उसके लिए डस्टसप्रेसन सिस्टम होगा। ट्रांसपोर्टेशन से उसके लिए रेगुलर पानी का छिड़काव किया जायेगा।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि प्रदूषण के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर सीमेंट इन्डस्ट्रीज है, तो आप उसका पहले पुख्ता ईलाज कराये, फिर पर्यावरण पर काम करें और आगे अपना काम शुरू करें, इसको लिखित में दें।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि पर्यावरण प्रबंधन के तहत जो भी सुरक्षा उपाय किये जायेंगे, पहले से योजना में भी दिया गया है, लिखित में आपका जो जवाब है।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(चम्प्यालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि ये लिखित में 25 प्रेसेंट भी नहीं है, कम है। नाड़ियों तालाब के बारें में मैंने एक ही चीज पढ़ी है, आपने सिर्फ 5 नाड़ियां ली हैं। जैसे हरिमा में तीन नाड़ियां हैं, भदानी गांव में 5-6 नाड़ियां हैं, डेह में 10 से अधिक नाड़ियां हैं, आपने सिर्फ 5 का मेशन किया है बाकि का नहीं। आसपास के गांवों की छोटी-बड़ी नाड़ियों की संख्या करें तो 75 से 100 के बीच में संख्या होगी।

पर्यावरणीय सलाहकार श्री रमेश नेहरा ने बताया कि आपकी बात बिल्कुल सही है, यह परियोजना की रिपोर्ट केवल ड्राफ्ट ईआईए रिपोर्ट है, आपके सुझाव के तहत फाइनल ईआईएमपी रिपोर्ट होगी उसमें ये सभी शामिल करके प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों के सुझाव के लिए यह जन सुनवाई रखी जाती है।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि हमें लिखित में चाहिए कि कम्पनी जय काम शुरू करेगी उससे पहले ये सभी कार्य करवायेंगे। दूसरी बात किसानों की जैसे मान लीजिए, जब आपका प्लांट चालू होगा, जिसमें माईनिंग एवं प्लांट से जो भी प्रदूषण होगा, जिन-जिन लोगों के खेती की जमीन आपने अधिग्रहण की है, उनको आप पैसे दे रहे हैं, परन्तु जिन-जिन लोगों के खेती की जमीन नहीं आ रही है, तो जब उसकी फसल खड़ी होगी और उस पर आपके पॉल्यूशन से उसकी पैदावार में जो कमी आयेगी, फाल-बगर आ रहा है, उस समय आपकी डस्ट उसके ऊपर से जायेगी तो उसके लिए आप क्या मुआवजा रखेंगे, प्रतिवर्ष उसको जो नुकसान होगा उसके लिए आप क्या रखेंगे?

श्री अरविन्द शर्मा, एवीपी इन्वायरमेंट कॉरपोरेट, जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड ने कहा कि आपके जितने भी सुझाव हैं वह नोट कर लिये गये।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि मेरे कोई सुझाव नहीं हैं, समस्याएँ हैं, निवारण चाहिए। सुझाव देने वाला मैं कौन हूँ? मेरी समस्याएँ हैं, इनका आप निवारण कीजिये।

श्री अरविन्द शर्मा, एवीपी इन्वायरमेंट कॉरपोरेट, जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं का निवारण किया जायेगा। जो पब्लिक हियरिंग के मीनट्स बनेंगे, उसके लिखित हम ईआईए रिपोर्ट में भी शामिल करेंगे एवं भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को वो रिपोर्ट हम भेजेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी

राज्य योजना आयोग, दिल्ली

(अध्यात्मिक जीवन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि आप गुमाने वाली बात कर रहे हैं। आप पर्यावरण के लिए अलग कमेटी बनायें जिसमें प्रत्येक गांव से 5-7 आदमी लीजिये, जिनकी जमीनें नहीं हो और जो आपसे प्रभावित नहीं हो, उनकी कमेटी बना कर उनकी देखरेख में आप ये काम कराये, जो आपकी भाषा थोड़ी समझे और गांववालों की भाषा समझे, उन आदमियों की कमेटी बनाये। उन लोगों की कमेटी मत बनाया जिनका आप जाते ही नाम ले और वो खुशी से आगे आ जाये, वो कम्पनी की ही सोचेगा, क्योंकि कम्पनी के लोग उसे वर्बली जानते हैं, हमें वो आदमी नहीं चाहिए। हमें पर्यावरण वाले शुद्ध किसान की प्रति गांव की कमेटी बना कर उनके निवारण के आधार पर काम कराये।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि ये ईआईए रिपोर्ट केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट है, आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायतें दी जायेगी, उन सभी को इसमें जोड़ा जायेगा तथा संदर्भ में उसके किये जाने वाले सुधार, वो भी इसमें अंकित किये जायेंगे और भी अपने शिकायत एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री शिवनाथ गोदारा निवासी खेराट ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रदूषित गैस CO_2 निकलेगी तथा CO_2 को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा वन चाहिए लेकिन वन लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि नहीं है, तो हमें प्रति बीघा या प्रति किलोमीटर क हिसाब से लगाने हैं तो कितने सघन वन लगे हैं, अब तक आपने कितने पौधे लगाये तथा भविष्य में कितने पौधे लगायेंगे, उन सब का आंकड़ा चाहिए। अभी डेह में जो नीम कॉरिडोर लगा है, उसके अलावा आपके लगे हुये पौधे नहीं देखे। सघन वन जापान की एक पद्धति का नया शब्द है मियावाकी।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि कम्पनी ने नीम कॉरिडोर एक किलोमीटर दर्शाया था, परन्तु वह मात्र 450 मीटर ही है। इन चीजों से थोड़ा बढ़ो। जो करते हो उससे सवा गुना या डेढ़ गुना मत लिखो।

श्री शिवनाथ गोदारा निवासी खेराट ने कहा कि पहला बिन्दु— CO_2 गैस को खत्म करने के लिए हमें सघन वन लगाने हैं, सघन वन हमारे लिये नया शब्द है। सघन वन जापान के मियावाकी की पद्धति है, जिसमें 3-4 फीट की दूरी पर पौधे लगाने होते हैं, एक निर्धारित एरिया जैसे 200X300 वर्ग फीट के क्षेत्र में उसमें कम-से-कम पांच सौ, सात सौ पौधे लगाने हैं। तो अब तक कम्पनी ने कितने सघन वन लगाये हैं तथा और कितने लगाओगे? अतः अभी जुलाई का टारगेट लेकर प्रत्येक गांव में कम-से-कम पांच बीघा में एक सघन वन लगावें।


क्षेत्रीय अधिकारी
पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग
नागौर (राजस्थान)


(गन्ध्यालाल जीनर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

दूसरा बिन्दु— जब प्लांट शुरू होगा तो उससे आने वाली डस्ट से खेतों की जमीन कम-से-कम प्रदूषित हो उसके लिए आप क्या करेंगे? मेरा सुझाव है कि किसान के साथ मिलकर रोहिड़ा एवं खेजड़ी जैसे पौधों का रोपण कर उसकी सीव मय कर ताकि डस्ट सीव पर ही रुक जाये और पूरी जमीन बर्बाद ना हो।

तीसरा बिन्दु— अभी आप द्वारा तालाबों का जिक्र किया गया, जब ये डस्ट उड़ेगी तो तालाब की अंगौर भूमि पर पड़ेगी तथा पानी के साथ बह कर तालाब में जायेगी, जिससे जल प्रदूषण होगा। तो उसे रोकने के लिए तालाब की अंगौर भूमि पर 100 मीटर चौड़ी हरित पट्टिका लगाई जाये ताकि डस्ट वहीं रुक जाये तथा पूरे अंगौर भूमि में भूमि प्रदूषण भी ना हो।

चौथा बिन्दु— परम्परागत जलाशयों के आप द्वारा क्या किया जायेगा, अभी आपने मात्र 4-5 नाड़ियां बतायी, जबकि सबसे बड़ा तालाब डेह का है या भदानी नाड़ी है, आपने बताया कि इनकी गहराई कर देंगे, तो गहराई करने की जरूरत नहीं है, इनका सौन्दर्यीकरण, घाट निर्माण किया जाये और इनकी अंगौर भूमि में हरित पट्टिका लगाई जाये।

पांचवा बिन्दु— जब प्लांट शुरू होगा तो एलर्जी एवं फेंफड़ों सम्बन्धित बिमारियां होगी, उसके लिए आप स्थानीय लोगों के लिए क्या बचाव करेंगे तथा प्राथमिक उपचार के लिए आप किस प्रकार सहयोग करेंगे, ये सब हमें लिखित में चाहिए।

छठा बिन्दु— आपने प्लांट के लिए जो भूमि आवाप्त की है, वहां जितने वन्यजीव थे या पक्षी थे, उस बैचारों को जगह छोड़नी पड़ी, उनके घरों को हमने बर्बाद किया है, तो उनके शरण के लिए आपने क्या प्रयास किया, वन्यजीवों के लिए कितने सघन वन लगाये हैं, उनके लिए कितनी तलाई या खेळियां बनाई हैं। आपने अभी बताया कि 10 खेळियों का निर्माण किया वो केवल गायों के लिए है। छोटी-छोटी तलाईयों का निर्माण भी करना पड़ेगा, ताकि हिरन, खरगोश, लोमड़ी, नीलगाय ये भी आराम से पानी पी सके।

सातवा बिन्दु— आपने खनन क्षेत्र हेतु किसी मंगरे की जमीन आवाप्त की है, तो वहां जो वन्यजीव प्रभावित हुवे हैं, उनके लिए आपने किसी अन्य जगह ऐसी जमीन आवाप्त की है, जहां वन्यजीव आराम से रह सके।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

आठवां बिन्दु— अभी आपने रेन हार्वेस्ट की बात की, भदाना, हरिमा तथा डेह के प्रत्येक घर में रेन हार्वेस्ट सिस्टम लागू किया जाये, जिसके लिए आपको ठोस निति अपनानी होगी, जिससे प्रत्येक घर का पानी नालियों के माध्यम से गलियों में ना बहकर जमीन में जाये। जिसके लिए शुरुआती चरण में चार-पांच गावों में ये कार्य करना पड़ेगा।

नौवा बिन्दु— ग्रीन एनर्जी में जैसे स्ट्रीट लाईट एवं अन्य है, शुरुआत में कम-से-कम दस गांव में आपके द्वारा ग्रीन एनर्जी पर कार्य शुरू होना चाहिए।

दसवां बिन्दु— स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दें एवं यहां के स्थानीय श्रमिक भी लें तथा उनके साथ ये भी ना हो कि अगले 1 साल बाद यहां के श्रमिकों को आप चितौड़ अथवा भीलवाड़ा भेज दो। स्थानीय श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुविधा, समुचित रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास के लिए अभी तक आपने क्या-क्या कार्य किया तथा भविष्य में आप क्या करोगे?

अतः मेरे सभी बिन्दुओं पर हमें ठोस लिखित में आपसे चाहिए।

श्री राधेश्याम भाकल, पूर्व सरपंच भदाना ने शायरी के साथ अपनी बात की शुरुआत कर जे.एस.डब्ल्यू. द्वारा भदाना तथा आसपास के क्षेत्र में करवाये गये कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि राजकीय विद्यालय, भदाना में तीन बड़े हॉल निर्माण कार्य, हरिराम बाबा मंदिर के सामने प्याऊ निर्माण कार्य, भदाना में सार्वजनिक तालाब निर्माण खुदाई कार्य, जिन्दास गांव में पेयजल ट्यूबवेल, सभी गांवों में 250 सोलर लाईट, श्री राधा कृष्णा गौशाला में निर्माण कार्य, जे.एस.डब्ल्यू. के दायरों में आने वाले सभी गांवों में गोबर गैस, हरे सब्जी प्लांट, स्कूलों में निर्माण-कलर, छत वाटर प्रुफ कार्य, महिला रोजगार सेन्टर, हेल्थ केम्प सेन्टर, आयुर्वेदिक सेन्टर जैसे बड़े केम्प लगाने के कार्य जे.एस.डब्ल्यू. द्वारा हुये हैं। इन कार्यों को देखते हुए हम सभी गांववाले, सभी किसान यहीं आशा रखते हैं कि आने वाले समय में जे.एस.डब्ल्यू. हमारे गांवों को विकास एवं रोजगार की ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। जे.एस. डब्ल्यू. प्लांट का हमारे गांव में स्वागत है, जिन्होंने आकर इतना विकास कार्य करवाये तथा आगे और कार्य करवायेंगे।

किसानों की तरफ से कुछ मांगें रखना चाहता हूं, जिन-जिन किसानों ने अपनी जमीन देकर जे.एस.डब्ल्यू. के सहयोग का काम किया है, उनका इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा योगदान है, उस सभी किसानों को प्राथमिकता दी जाये। आज तक

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

1
(चन्मालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

उन किसानों का कोई कार्य नहीं हुआ, ना उनका साधन लगा, ना उन्हें रोजगार मिला। अतः उन किसानों के लिए कुछ कम्पनी के द्वारा किया जाये। कम्पनी के दायरों में आने वाले गांवों में 100 से 200 लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में योग्यता, वरियता अनुसार रोजगार दिया जायेगा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल समस्या है, यहां एक छोटा सा हॉस्पिटल है, जिसमें डिलिवरी के सबसे ज्यादा केस हैं, ट्रिटमेंट लेने के लिए नागौर अस्पताल जाना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है तथा इसमें एक रेलवे फाटक भी आ रहा है, हमें कभी कभार बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अतः यहां भादना-जिन्दास में एक बड़ा हॉस्पिटल निर्माण कार्य हो।

शिक्षा में जब 10वीं-12वीं के बच्चे उर्तीण होने पर उन्हें आगे की शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, अतः यहां एक बड़ा कॉलेज निर्माण कार्य हो जिससे किसानों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आसानी हो। पानी को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है, दो सप्ताह अथवा एक सप्ताह से मात्र 100-200 लीटर पानी आता है, काफी घर वंचित भी रह जाते हैं। जे.एस.डब्ल्यू. अपने प्लांट से भदाना, जिन्दास के गांवों को पानी तथा बिजली दें। किसानों की एक और समस्या, जो काफी समय से सुनने में आ रही है, जे.एस.डब्ल्यू. में जो भी छोटी बड़ी कम्पनियां आई हैं, जो जुड़ी है, उनमें जो साधन जैसे- ट्रैक्टर-ट्रोल्ली, जे.सी.बी., डम्पर हैं, वो रावरी ज्यादा बाहर के लगे हुवे हैं, अतः जे.एस.डब्ल्यू. से मेरा निवेदन है कि स्थानीय गांवों के साधन सबसे पहले कम्पनी में लगवावें। ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जिन्दास में सामुदायिक भवन निर्माण करवावें। जिन्दास का वर्षादित पानी जिन्दास में रह जाता है, अतः इस पानी को बाहर निकलवाने का काम भी करवावें।

श्री सहीराम बाना निवासी भदाना ने कहा कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत भदाना तथा आसपास के गांवों में ज्यादा से ज्यादा पेड़-पौधे लगाये जायें, तथा उन पेड़-पौधों की समय से देखरेख भी की जाये। क्योंकि विगत वर्ष जे.एस.डब्ल्यू. ने भदाना फांटा से गांव तक पेड़-पौधे लगाये तो थे परन्तु देखरेख के अभाव में सभी क्षतिग्रस्त हो गये। ग्राम भदाना को विशेष ध्यान में रखते हुए गांव में सिवरेज लाईन का निर्माण किया जाये तथा गांव में आरओ लगाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करावें। लड़के-लड़कियों के शिक्षा के लिए गांव में पुस्तकालय का निर्माण किया जाये। जिन लोगों ने कम्पनी को अपनी जमीन दी है, उन लोगों को आप विशेष रोजगार का अवसर दें, और उन्हें अपने वाहन लगाने दें। जब एक ही


अनिल कुमार
 अध्यक्ष, ग्राम प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 नागौर (राजस्थान)


 (कम्पलास जीनगर)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 नागौर

आदमी 4-5 वाहन लगा लेता है तो बाकि लोग कुछ नहीं कर पाते, अतः ये भी ध्यान में रखे कि एक आदमी को एक अथवा दो वाहन से अधिक ना लगवाये। गांव भदाना तथा जिन्दास में बिजली की समस्या के समाधान हेतु प्लांट की लाईन से दोनों गांवों को जोड़कर बिजली आपूर्ति की जाये। योग्यतानुसार स्थानीय रोजगार प्रदान किया जाये। कम्पनी को दो साल तो हो गये हैं परन्तु अभी तक तो यहाँ रोजगार के अवसर नहीं मिले, कुछ चुनिन्दा लोगों को ही फायदा दिया जा रहा है। भदाना में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र है, आबादी को ध्यान में रखते हुए इसके नवीन भवन का निर्माण तथा एक एम्बुलेंस सुविधा कराये। खेल मैदानों का विस्तारपूर्वक कार्य करवावे। ग्राम पंचायत की सड़कों कम्पनी के भारी वाहनों के चलने से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है, इसके लिए कम्पनी को काफी बार अवगत किया है कि आप सड़कों को पूर्णरूप से सुदृढ़ करें। सीमेंट प्लांट की बाउण्ड्री के आसपास के खेत, भदाना की नाड़ी तथा एक प्लांट के पास ही और नाड़ी है, तो उन नाड़ियों का पानी प्रभावित नहीं हो, तथा किसानों की फसल भी नष्ट नहीं हो। इन सब के लिए कार्यवाही करवाये।

श्री मानवेन्द्र सिंह निवासी हरिमा ने कहा कि जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी ने कुछ अच्छे प्रयास किये हैं, जैसे हमारे गांव में सोलर लाईट लगाना, सिलाई केन्द्र की शुरुआत, प्रोजेक्ट तरंग तथा प्रोजेक्ट उमंग इत्यादि प्रयास किये हैं। इसके अलावा इन्होंने रेडियम बेल्ट का अभियान चलाया इन सब के लिए इनका धन्यवाद करते हैं। परन्तु हमारी कुछ महत्वपूर्ण समस्या एवं मांगें हैं, जिन्हें आगामी समय में कम्पनी द्वारा पूरा किया जाये। कम्पनी द्वारा हरिमा के मुख्य मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है, उस मार्ग पर सी.सी. रोड का निर्माण किया जाये। गांव के समस्त मंदिरों का जिर्णोद्धार किया जाये, गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाये तथा कम्पनी उसमें अपना पूर्ण सहयोग करें। गंदे पानी की निकासी के लिए गांव में सिवरेज सिस्टम का प्रबन्ध करें। खनन कार्य गांव से थोड़ा दूर किया जाये जिससे गांववालों को परेशानी ना हो, हरिमा गांव के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाये, जिससे प्रदूषण से पर्यावरण नुकसान ना हो। युवाओं को रोजगार दिया जाये, कम्पनी कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये, गांव में खेल स्टेडियम बनाकर उसमें लाईट की व्यवस्था की जाये। गांव की समस्त गलियों में स्ट्रीट लाईट लगाये, पहले भी कम्पनी ने लगाई है, परन्तु हम उम्मीद करते हैं कि कम्पनी और कार्य करें। खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव के खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया जाये। गांव में लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग आधुनिक लाईब्रेरी बनावे। गौशालाओं में 12 महीने के चारे-पानी की व्यवस्था तथा टीनशेड का निर्माण करें। गांव में


क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 नागौर (राजस्थान)


(चम्पालाल जीनगर)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 नागौर

जलाशयों के मरम्मत तथा गांव की मुख्य नाड़ी का सौन्दर्यकरण किया जायें। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नये कमरे निर्माण तथा बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाये। महिलाओं को रोजगार के उचित अवसर दिये जाये, गरीबों के लिए वर्षाजल संग्रहण हेतु टांकों का निर्माण किया जाये, गरीबों के मकान बनाने हेतु सहायता राशि दी जाये तथा नहरी पानी की सप्लाई हर घर हेतु बूस्टर व्यवस्था करें। आंगनवाड़ी में दो कमरे निर्माण, फर्निचर एवं अन्य आवश्यक वस्तु उपलब्ध करायें, हरिमा में गवाड़ का सौन्दर्यकरण करें, हरिमा की सभी मुख्य गलियों में रोड़ बनाई जाये तथा गांव के प्रमुख चौक-चौराहे का सौन्दर्यकरण करावें। गांव के सरकारी विद्यालय में इनडोर स्टेडियम बनाया जाये, जिसमें जिम व्यवस्था भी हो। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं विकास हो, जे.एस.डब्ल्यू. का काम भी चले, लेकिन गांव का भविष्य एवं हक सुरक्षित रहे। कम्पनी हमारी मांगों पर ध्यान दें एवं सीएसआर के तहत कार्य करावें। अगर कम्पनी एवं गांव साथ चले तो विकास भी होगा तथा विश्वास भी बढ़ेगा।

श्री हीराराम निवासी मांझावास ने कहा कि मेने अपनी जमीन जे.एस.डब्ल्यू. को इस शर्त पर दी थी एक कम्पनी एक आदमी और एक वाहन लगायेगी, परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने सभी से निवेदन करते हुए कहा कि अभी पहली जनसुनवाई चल रही है, दो और जनसुनवाईयां आयोजित की जायेगी। अतः इस जनसुनवाई के सन्दर्भ में आपके जो भी सुझाव अथवा शिकायत है, वो दर्ज कराये।

श्री पप्पूनाथ योगी निवासी हरिमा ने कहा कि जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी द्वारा पर्यावरण के सम्बन्ध में प्लांट की स्वीकृति पूर्व में ले ली एवं अभी और पर्यावरण स्वीकृति लेने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए आपने अब तक क्या काम किया? आपने पेड़ कहां लगाये? कई तो अखबारों में छपा कर अभी हमारे सामने पेश कर रहे हैं। आपको पर्यावरण के लिए धरातल पर कार्य करना चाहिए। हमारे आसपास के क्षेत्र निवासी, पशु-पक्षी, पेड़-पौधों के बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं पिछले 20 वर्षों से पर्यावरण को बचाने हेतु कार्य कर रहा हूं आपको स्वीकृति से पूर्व धरातल पर पेड़-पौधे लगाकर नियमित पानी डालना, पक्षियों के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लगातार इस एरिया में पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि कम्पनी द्वारा एनजीओ के मार्फत जो कार्य किये जा रहे हैं उनका रिजल्ट हमें मिले। तभी हम इस क्षेत्र के पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों तथा आम जीवन को बचा पायेंगे तथा प्रदूषण से हमें राहत मिल पायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जयपुर (राजस्थान)

(धनपाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर

सुश्री मोनिका राठौड़ निवासी सरासनी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी महादेय को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि हम ग्रामवासी जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट संयंत्र एवं खनन परियोजना के प्रस्तावित स्थापना कार्य का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि इस परियोजना के आगमन से क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक विकास के नये अवसर सृजित हुवे हैं। जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी द्वारा क्षेत्र में सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं, जैसे कि सरासनी विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आधारभूत ढांचे का सुदृढीकरण किया गया है। महिलाओं हेतु कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गई है, गांव में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई है, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनवाड़ी केन्द्र का जीर्णोद्धार एवं सेवाएं सुदृढ की गई, पेयजल सुविधा हेतु बोरवेल की स्थापना की गई है, इन प्रयासों के अतिरिक्त हमने पूर्व में कम्पनी में स्थानीय परिवहन सेवा हेतु बस सुविधा की भी मांग की थी, हमें ये अवगत करवाते हुए प्रशंसा हो रही है कि जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट द्वारा इस पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से बस सेवा के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है, किन्तु खेदपूर्वक सूचित करना पड़ रहा है कि परिवहन विभाग द्वारा अब तक सरासनी गांव के लिए बस मार्ग की स्वीकृत नहीं किया जिसके कारण बस सेवा प्रारम्भ नहीं हो पाई। हम राजस्थान सरकार एवं परिवहन विभाग से विनम्र आग्रह करते हैं कि सरासनी गांव का बस मार्ग शीघ्र खोल दिया जाये ताकि इस सेवा का लाभ स्थानीय ग्रामीणों को मिल सके। ये न केवल क्षेत्र की आवागमन सुविधा को सुदृढ करेगा, बल्कि सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन देगा। हम आपके माध्यम से पुनः इस परियोजना के प्रति अपना समर्थन प्रकट करते हैं। आशा करते हैं कि आपके सहयोग से ये पहल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपरिथत जन-मानस को प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः आमंत्रित किया।

श्रीमती प्रिया निवासी भदाना ने कहा कि हमें जे.एस.डब्ल्यू. से रोजगार मिला तो हमें खुशी भी है। परन्तु रोजगार अभी उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। क्योंकि हम राजीवीका की 120 महिलाएं भदाना से हैं, लेकिन अभी तक भदाना में एक ही सेन्टर खुला है, जिसमें केवल 20 महिलाएं काम कर रही हैं, अभी तक 100 महिलाओं को रोजगार की जरूरत है, उनके लिए कम-से-कम तीन सेन्टर और खुलवावें। हमारे गांव की बेटियों को लाईब्रेरी में पढ़ने के लिए नागौर जाना पड़ता


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य पदधन नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


(ज्योत्सल जंगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

है, जिससे बेटियों को परेशानी होती है, अतः गांव की बेटियों के लिए गांव भदाना में एक लाईवरी बनवावें।

श्री महावीर प्रसाद शर्मा निवासी डेह ने अपने लिखित मांग पत्र को पढ़ते हुए कहा कि "जनसुनवाई में निम्न बिन्दुओं का निवारण कर आम जनता को राहत दिलवाने बाबत। श्रीमान जी, प्रार्थीगण की ओर से विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि ये एक सीमेंट के उत्पादन के समय जिस प्रकार मूण्डवा में संचालित प्लांट से प्रदूषित फैक्ट्री का धुंआ रात्रि में तीव्र गति में चालू होता है एवं पूरे गांव में घरों की छत तक भारी डस्ट एवं सीमेंट के कण जमा हो जाते हैं, हर घर पर 5-10 किग्रा सीमेंट की डस्ट जमा हो जाती है तथा खेती में डस्ट लगने के कारण बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता है और सारी कृषि उपयोगी भूमि बंजर हो जाती है। वर्तमान में आपके द्वारा लगाया गया प्लांट से भी यही स्थिति ग्राम भदाना तथा आसपास के गांव में होनी है, जिसके उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु जिस प्रकार के उपाय करवाये जाये, इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों को अवगत करवाये। ग्राम डेह में एक बड़ा तालाब स्थित है, जिससे करीब 50 गांव के लोग मीठा पानी पीते हैं, साथ में पशु-पक्षी एवं मवेशी भी पानी पीते हैं। पशुओं के लिए पानी लोग कोठी, टेंकर से ले जाते हैं, अगर इस तालाब का प्रदूषण बढ़ा तो क्षेत्र की समुचित जल व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होगी और पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो जायेगा। इसके अतिरिक्त डेह गांव के आसपास खनन क्षेत्र में साइलेंट ब्लॉस्टिंग के दौरान जमीन में होने वाले कम्पन में लगभग 5000 घरों की संरचनात्मक स्थिरता को खतरा है, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 18 हजार है, जिनके घरों को नुकसान पहुंचाने की पूर्ण सम्भावना है, पूर्व में भी नागौर जिले में संचालित फैक्ट्रीयों के आसपास के गांवों में ऐसी स्थितियां देखने को मिल चुकी है, जो हमारी चिंता को और प्रमाणित बनाती है। अतः हम इस परियोजना से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। इन समस्याओं के निराकरण में आम जनता को आप अवगत कराये।

गांव में अस्पताल मुहैया करवाने एवं स्पेशल ट्रिटमेंट की व्यवस्था करवाये। सीमेंट फैक्ट्री एरिया में रहवासियों को टीबी की समस्या अत्यंत होती है एवं माईनिंग के साइलेंट ब्लॉस्टिंग के कारण जमीन के अन्दर ही कम्पन होकर ग्रामीण मकानों में दरारें आ जाती है, इस समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में भी आमजन को वक्तव्य। विकास कार्य में गांव के लोग उक्त कमेटी में कितने होंगे, यह स्थिति भी आप स्पष्ट करावें कि डेह गांव से इतने मनोनित व्यक्ति है, जिनको इस बार में लिया

श्री श्री आनंदजी

गांव के लोग निम्नलिखित कार्य करवावें (समस्या)

(चम्पादाज जीनर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

गया है। विकास कमेटी में हर जाति वर्ग के 10-20 आदमी तय किये जाये एवं विकास राशि कहां लगनी है, इसका निर्णय भी कमेटी के द्वारा सुझाये गये स्थान पर ही किया जावे। नजदीकी एरिया के कितने लोग प्लांट के एरिया में रोजगार के लिए लगाये जायेंगे, उक्त तथ्यों से आम लोगों को अवगत कराया जाये कि डेह के इतने लोगों को रोजगार दिया गया है, क्योंकि डेह से काफी जमीन प्लांट को दी गई है। गौशाला एवं गांव के विकास संस्थाओं को किस प्रकार सहयोग दिया जाये। फैक्ट्री के कारण बंजर होने वाली भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने हेतु कम्पनी किस प्रकार किसानों की सहायता करेगी। कृषि समुदाय के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु किस प्रकार की योजना लागू की जायेगी। गांव में स्थित विकास संस्थाओं, गौशालाओं एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं का कम्पनी द्वारा क्या सहयोग किया जायेगा। स्थानीय निकाय में किस प्रकार से भागीदारी रहेगी। कम्पनी प्लांट एवं माईनिंग क्षेत्र में स्थानीय लोगों को कितने प्रतिशत नौकरी दी जायेगी, यह नौकरियां किस प्रकार, किस स्तर, श्रमिक, सुपरवाइजर या अधिकारी आदि की होगी, इस बारे में भी अवगत करायें। जल स्रोतों पर प्रभाव एवं उसके समाधान, खनन और संयंत्र संचालन से भू-जल स्तर में गिरावट आ सकती है, ऐसे में कम्पनी को स्पष्ट करें कि जल संरक्षण एवं पुनर्भरण में कौन-कौन से कदम उठायेगी, जिससे पानी का स्तर ऊंचा उठे। स्वास्थ्य शिविर एवं क्लिनिक की स्थाई व्यवस्था किस प्रकार की जाये, सामाजिक ढांचे और सांस्कृति धरोहर की सुरक्षा एवं गांव में एक-एक धार्मिक स्थानों एवं विद्यालयों, आंगनवाडियों, सांस्कृति धरोहरों की रक्षा हेतु कम्पनी की क्या नीति होगी। आवाजाही से गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, बच्चों-वृद्धों को खतरा होता है, इसके लिए कम्पनी की क्या वैकल्पिक मार्ग या सुरक्षा उपाय अपनायेगी। सीएसआर के अन्तर्गत कम्पनी किन-किन क्षेत्रों में काम करेगी, उसकी वार्षिक योजना क्या होगी, स्थानीय जनता को कैसे जानकारी दी जायेगी, ये भी स्पष्ट करें। शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना होनी चाहिए, जहां ग्राही अपनी समस्याएं सीधा दर्ज करवा सके, जिससे कम्पनी को अवगत करा सके। गांव में वर्तमान में लगभग 6-7 बड़े विद्यालय संचालित हैं, इनमें तीन सरकारी एवं शेष निजी विद्यालय हैं, इनके अतिरिक्त यहां दो महाविद्यालय भी स्थित हैं, बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में संयंत्र से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण एवं कम्पन से बच्चों के स्वास्थ्य एवं एकाग्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः स्पष्ट किया जाये कि शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या सहयोग दिया जायेगा, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाये जायेंगे।


जिला अधिकारी
 जिला प्रमुख निवास भवन
 जयपुर (राजस्थान)


 (चम्पालाल जीनगर)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 जयपुर

अतः उपरोक्त समस्याओं का हल ढूँढ कर आम जनता को राहत दिलाई जाये, समस्या का निदान करवाया जावे तथा आम जनता को अवगत कराया जाय कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा और कितने दिनों के बीच में होगा। उक्त समस्याओं का समाधान नहीं होने की स्थिति में इस औद्योगिक प्लांट का विरोध करते हैं।

श्रीमती प्रिया निवासी भदाना ने पुनः कहा कि माफी चाहूंगी क्योंकि गांव की बहनों की मुख्य समस्या का मैं भूल गई थी। पिछली बार भी हमारी मांगें थी, जो राबर्स दड़ी समस्या आ रही है। हम राजीविका से जुड़े 10 एसओजी हैं, जिनमें 120 महिलाएँ हैं, हमारी पहली मीटिंग तो होती है ग्रुप में, जैसे 10 महिलाओं के बीच में होती है, वो तो अपने-अपने घर में जहां पर भी जगह मिलती है, वहां कर लेते हैं, लेकिन मुख्य होता है ग्राम संगठन ऑफिस, जो कोई बड़ा भवन हो, जिसकी हमारे गांव में व्यवस्था नहीं है, जे.एस.डब्ल्यू. से हमारी बात हो गई, परन्तु वो बोला है जमीन की समस्या है, तो मैं सरपंच साहब और कलेक्टर साहब से हमारे गांव की सभी बहनों, महिलाओं की तरफ से भांग करती हूँ कि भदाना के आईटी सेन्टर के पास की सार्वजनिक जमीन थोड़ी सी हमें भवन हेतु आवंटित करावें, जिससे हमारे ग्राम संगठन के लिए सामुदायिक भवन बन सके।

श्री भजनलाल पारीक, प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। मैं शिक्षा से जुड़ा होने के कारण, जिन्दास क्षेत्र में दो राजकीय विद्यालय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक संचालित हैं। विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के लिए जे.एस.डब्ल्यू. परिवार से हम आशा करते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में एक शानदार पुस्तकालय के लिए कक्षा कक्ष मय पुस्तकें एवं बालिकाओं के लिए आधुनिक शौचालय की व्यवस्था की मांग करते हैं। जिन्दास गांव एससी बहुल्य है, इनके जीवन स्तर को उठाने के लिए बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना अति आवश्यक है, इसलिए आशा करते हैं कि जे.एस.डब्ल्यू. प्लांट से रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में विकास की जो संभावनाएँ बनी हैं, कि विद्यालय को सुरक्षित कर कक्षा-कक्षा, पुस्तकालय एवं बालिकाओं के लिए अत्याधुनिक शौचालय निर्माण करवाया जाय। प्राथमिक विद्यालय में पानी का टांका निर्माण, अभी बने कक्षा-कक्ष के पास एक और कक्षा-कक्ष निर्माण, दोनों ही विद्यालयों में पेड-पौधे एवं किचन गार्ड की व्यवस्था करावें।


 क्षेत्रीय अधिकारी
 राजस्थान राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय
 जयपुर (राजस्थान)


 (सम्पालाल जीनगर)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 जयपुर

श्री प्रमोद, एकलव्य फाउण्डेशन एनजीओ प्रतिनिधि ने कहा कि मैंने कहाँ-कहाँ पढ़ा था कि बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ, फैक्ट्रियाँ लगती हैं एवं अपना काम करके चला जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कमाल हो रहा है कि जनता एवं इण्डस्ट्री आमने-सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, और अपने-अपने मुद्दे रख रहे हैं। किसी भी तरह के विकास में दोनों तरह की बातें होगी, कुछ हमें क्षति होगी, साथ में विकास भी होगा। और यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें इण्डस्ट्री के इवेलइम्पेंट का समझना भी होगा एवं उसका साथ देना होगा। साथ में हम इस बात की ओर ध्यान दें कि जो क्षति हो रही है, वो कम से कम हो और उन दायरों में जिसके लिए भारत सरकार ने अपने नियम बनाये हैं।

श्री मनोज कुमार सोनी, प्रधानाचार्य, राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय भदानी ने कहा कि जे.एस.डब्ल्यू. परिवार की तरफ से हमारे विद्यालय में बहुत विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। तीन कमरों के अलावा पर्यावरण की दृष्टि से हमारे विद्यालय में गत वर्ष 50 पेड़ मय ट्रीगार्ड उपलब्ध करवाये गये और समय-समय पर उनके द्वारा अनेक गतिविधियाँ बच्चों के विकास के लिए करवाई जा रही हैं। वर्तमान में विद्यालय में समर कैम्प आयोजित हो रहा है, गत वर्ष की थीम पर इस वर्ष भी बच्चों के लिए समर कैम्प चल रहा है। साथ में गांव में जो समस्याएँ हो रही हैं, गांव में भू-भ्रांतियाँ हैं कम्पनी को लेकर कि पॉल्यूशन बढ़ेगा। मेरी कम्पनी से उम्मीद है कि वे अत्याधुनिक टेक्नॉलोजी का प्रयोग करते हुए पॉल्यूशन कम-से-कम करेंगे। ये प्लांट लगेगा, ये नवीनतम टेक्नॉलोजी युक्त होगा, जिसमें पॉल्यूशन की सीमा कम रहेगी। लेकिन कम्पनी को भी मेरी तरफ से सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करावें और उनकी केयर करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में होने वाली पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकें। साथ ही कम्पनी द्वारा ग्राम सरासरी, भदानी डेह, हरिमा, जिन्दास में जो विकास कार्य करवाये जा रहे हैं, उनके अवलोकन का भी हमें श्रेय मिलता है, ये विकास कार्य शिक्षा, रोजगार के साथ-साथ गांव के विकास से सम्बन्धित है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कम्पनी के यहाँ स्थापित होने से इस क्षेत्र के विकास को नये आयाम मिलेंगे, साथ ही हमारे भाईयों को नया रोजगार मिलेगा।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि बाहर ये जो भी उद्देश्य है उसकी उपस्थिति करवा रहे हैं, जब इन्होंने पर्यावरण पर कोई काम किया ही नहीं है, उससे पहले ही यह गांव वालों के साईन करवाकर स्वीकृति करके ये डाटा ले रहे हैं, ये सही नहीं है, ये स्वीकृति के रूप में गिने जायेंगे, इनसे निवेदन करें कि ये

क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नवीर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नवीर

उपस्थिति बंद करें एवं इस तरह से पहले डाटा कलेक्शन नहीं करें। पहले काम करें और फिर अपना डाटा कलेक्शन करने का प्रयास करें। ये डाटा आगे काम में लेंगे, यह कह रहे हैं कि इन्होंने इतने लोगों की उपस्थिति में स्वीकृति से ये काम करवाये हैं, अभी धरातल पर 1 प्रतिशत भी इनका काम हुआ ही नहीं है। तो आप क्यों डाटा पहले कलेक्ट कर रहे हैं, वो स्वीकृति में काम नहीं ले उसे बंद कराया जाये। इसका प्रत्युत्तर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने बताया कि आपकी यह बात का स्वागत है, पब्लिक हियरिंग का मतलब ये होता है कि इस पब्लिक हियरिंग में जो भी लोग आते हैं, उनका एविडेंस ये उपस्थिति होता है। पर्यावरण स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का एक सिस्टम है, अगर पर्यावरण विभाग किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री को अनुमति देता है तो उसकी एक गाइडलाइन बनी हुई है, उस गाइडलाइन की पालना उसे करनी है। उन्होंने इस गाइडलाइन की पालना के लिए क्या-क्या प्रावधान किये हैं तथा उनसे क्या चुक चुकी है, यह बात कहने-सुनने के लिए पब्लिक हियरिंग होती है। बहुत सारी चीजें पता केवल स्थानीय लोगों को होती हैं, उनकी बात भी इसमें सुनी जाती है, अगर कहीं चुक रह गई हो, तो आप लोगो से जो सुझाव आते हैं, कोई ढाणी, तालाब, नाली अथवा कोई विकास काम छूट गया हो तो वो इसमें दर्ज होता है। ये रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी जायेगी और उनकी गाइडलाइन में स्थानीय लोगों की क्या मांग आई है, पर्यावरण, रोजगार एवं डवलपमेंट के लिए, इनमें उसको निर्देश कर देंगे कि इस गाइडलाइन, एसओपी एवं स्थानीय लोगों की मांग के अनुरूप आप काम करें। इसके साथ सशर्त अनुमति देते हैं, इसीलिए ये साईन होते हैं, इसमें स्वीकृति देना या नहीं देना इसके लिए ना तो आपके पास अधिकार है और ना मेरे पास कुछ पॉवर है, ये तो भारत सरकार के पास ही पॉवर है, वो पर्यावरण स्वीकृति को भले रद्द करे या भले स्वीकार करें।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि हमारा निवेदन है कि आप पहले धरातल पर काम कराये और फिर इस प्रकार का डाटा कलेक्ट करें, ये मैं इस एरिया का निजी होने के कारण ही कह रहा हूँ और जो भी यहां साइन कर रहे हैं उनसे भी नहीं कर रहा हूँ कि साईन तभी करे कि इन लोगों ने यह काम किया है, काम अभी इन लोगों का कुछ नहीं है, डेह गांव में पिछली बार इन्होंने जो पेड़ लगाये हैं, उनके 450 मीटर का नीम कॉरिडोर उनके अलावा एक भी जिन्दा पौधा नहीं है। नीम कॉरिडोर के लिए इन्हें जो टीम मिली है, वो पर्यावरण के प्रति एक सजग टीम है। इनका रोज सिर्फ पौधे मुहैया करना था, पानी भी वहीं टीम मुहैया कर रही है, तो पानी भी इनकी तरफ से नहीं है तथा उसके नीचे बून्द-बून्द सिंचाई की व्यवस्था

श्री कैलाश गौतम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजस्थान सरकार

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजस्थान

भी इन्होंने नहीं करवाई है, ये केवल अपना श्रेय ले रहे हैं कि हमने नीम कोरिया बनाया है, जाली पर आपका नाम है एवं केवल पेड़ आपने दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। रखवाली के लिए भी आपने आदमी नहीं रखा, तीन-चार बार पेड़ों की जालियों की चोरी हुई, उसके लिए भी गांव वालों ने ही संघर्ष किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये डाटा, ये साईन बाद में ही कलेक्ट कीजियेगा, गांव वालें भोले-भाले, सीधे लोग हैं, इतने समझदार नहीं होते। जिसके प्रत्युत्तर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने बताया कि गांव वालों के लिए आप और भी ऐसे लोग भी हैं जो इनकी बात सुने एवं रिकॉर्ड करें, चूंकि अभी तक पहली जन सुनवाई में तकरीबन 30-35 लोगों ने अपनी बात रखी है, जिसमें विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सीएसआर एक्टिविटी की, स्थानीय रोजगार, प्लांट के स्थानीय लोगों के संसाधन लगे, महिलाओं एवं बच्चियों ने रोजगार एवं लाईब्रेरी की बात की है। इनके अलावा और भी किसी के सुझाव अपना शिवालय है तो उनको करें। इसके बाद 1 बजे दूसरी जन सुनवाई तथा 4 बजे तीसरी जन सुनवाई है।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि आपने ब्लॉक 3सी1, 3सी2 एवं 3डी1 में जिस जगह की पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी है, वहां इस पूरे प्रांगण, पाण्डाल में क्या कहीं पर नक्शा लगाया? अथवा किसी आम नागरिक को जानकारी नहीं है कि इस जगह ये खनन करेंगे और पेड़ काटेगे। जिस प्रकार यहां भवानी राज पंचायत, अमरपुरा ग्राम पंचायत के द्वारा स्वागत के बैनर लगाये हैं ना, उसी प्रकार यहां आपको ये नक्शे भी लगाने थे, इन डिस्ट्रिक्ट में एक पर प्रमानेंट वहीं होना चाहिए। जैसे आप यहां की जनता को अनाथ करने जा रहे हैं, यह धरती हम किसानों की माता है, जो आप लेकर हमें अनाथ करना चाह रहे हैं, तो हमें माफ़ तो होना चाहिए कि इस जगह पर अनाथ हो रहे हैं। इनके बताये गये डिस्ट्रिक्ट में एक भी खसरा नम्बर बता सकता है क्या कोई, क्या इनमें गांव का नाम दिया जा सकता है?

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार को निर्देशित करते हुए कहा कि इस पहली जन सुनवाई में कौन-कौन से एरिया प्रभावित होंगे, अनाथ बताये। रामकुमार जी आपकी बात नोट कर ली गई है एवं इसको हम ठीक कर देंगे।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने पुनः कहा कि पहले सिग्नेचर बंद कीजिये, एडीएम साहब आप कम्पनी तथा हमारे बीच में गिडिएटर है, जब तक वो बैनर बनकर नहीं आ जाते तब तक वो सिग्नेचर वाला रजिस्टर यहां आना चाहिए। अगर एक मिनट लगेगी, मैं ही वो बन्दा हूं जिसने हरिमा में पाण्डाल खाली करवाया था।

केन्द्रीय अधिकारी
पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण सचिव
कानपुर (राजस्थान)

(धनपाल जीनवर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कानपुर

वा आगे कया सवाते है, उस समय तो मैं अकेला था, आज तो हमारे साथ बेनिवाल साहब है। सिनेचर वाला रजिस्टर आपके पास आ जाय और उस सिनेचर रजिस्टर की पूरी पीडीएफ फाईल अभी साईन करके वो हमें यहां मिलनी चाहिए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि जो भी नियम संगत होगा वो करेंगे। आपने अपनी बात रखी है, इस पर थोड़ी देर में विचार करके डिसीजन लेते हैं। कोई भी डिसीजन ऐसी हाथों-हाथ नहीं ले सकते।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिभा ने पुनः कहा कि यहां किसी को मालूम है क्या कि यह खसरा किसका जा रहा है, किसका खेत जा रहा है, किसकी ढाणी जा रही है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि आपने अभी बात कही है ना, आप अपने सैकेण्ड जन सुनवाई के लिए देख रहे हैं, कि किस प्रकार करवाई जा सकती है। आप और कोई बात बताये ताकि हम आगे बढ़ सकें।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि इनकी बात बहुत गंभीर मुद्दा है। सर्वप्रथम आज का वातावरण इस जिले में जो चल रहा है, एक तरफ हम भारतीय न्याय संहिता बी.एन.एस. 2023 की बात करें, कलेक्टर साहब ने एक अखबार निकाला कि 20 जून तक धारा 163, जो पूर्व में धारा 144 लगती थी, जिसमें काइ भी सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकते। अभी मैंने आते ही सबसे पहले यहीं पूछा कि कम्पनी ने अनुमति तो ली है, लेकिन उस अनुमति को भी कम्पनी को अखबार में छपवाना चाहिए था, वरना लोग तो आये ही नहीं, एक तरफ तो आप समर्थन पत्रों के माध्यम से कह रहे हो कि पांच से ज्यादा व्यक्ति कहीं इकट्ठा नहीं जा सकते और दूसरी तरफ आप बिना कोई ऐसी सूचना के कि कम्पनी ने इसका परमिशन ली है, आप कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हैं, अभी पूरे जिले में 20 जून तक 163 का चल रहा है, इनकी बात का भी समर्थन है एवं अगर सूचना होती तो हजारों की तादाद में आते यहां लोग। आप मुझे बताईये जैसे 163 जनसुनवाई कर रहे हो, यहां मुझे भी पता नहीं कि आप कौन-कौन से ब्लॉक की जनसुनवाई कर रहे हो, तीन अखबार में अलग-अलग तारीख में आपने उसका पता दे दिया, एक में 3सी1 बता दिया, एक में 3सी2 बता दिया, किसी में 3डी1 बता दिया, यदि आप एक अखबार के अन्दर भी सम्मिलित रूप से यह बताते कि तीनों ब्लॉकों की हम जन सुनवाई करेंगे, तो लोगों को ज्यादा सहूलियत भी होती, लोग तैयारी करके भी आते। अभी एनजीओ के विद्यवान वक्ताओं ने अपनी बात कही,


श्री रामकुमार सोलंकी


(बेनिवाल जी.नगर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उनका अलग इंटरेस्ट होता है, जो राजीवीका से हमारी बहिन प्रिया जी ने बात कहीं रोजगार की, तो रोजगार इसके अन्दर दिख रहा है जो जब पिछली जन सुनवाई के अन्दर जन सुनवाई हुई थी। मुझे पता है आपको तो यहाँ से भी रिपोर्ट ही भेजनी है, क्योंकि कम्पनी इतनी बड़ी है तो मुझे नहीं लगती कि अगर लोगों की इतनी हैसियत बन पायेगी, आप इस कम्पनी के खिलाफ एक शब्द भी लिख दो। पिछली बार जो बात हुई थी, जब अंजुजा सीमेंट की बात आई थी जो आरओ साहब को स्थगित करने का लिखा था, क्योंकि भारत सरकार के माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी का 22.11.2025 का एक लेटर है।

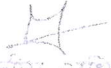
श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने पूर्व एमएलए साहब का ध्यान अपनी ओर करवाते हुए कहा कि इन्होंने मीटिंग कहाँ रखी है तथा ब्लॉक कहाँ के है, यहाँ से सिग्नेचर हो जायेंगे और वहाँ पर पास हो जायेंगे। जहाँ ब्लॉक है उन लोगों को मालूम ही नहीं है। जिन गांवों के अन्दर ब्लॉक्स हैं उन गांवों में इन नाटिश या फ्लेक्स बैनर आदि लगवाने चाहिए थे, किसी भी गांव हरिमा, सरासनी, भदामा डेह में कहीं भी इस सूचना हेतु सार्वजनिक बोर्ड अथवा बैनर नहीं लगाया। मारवाड़ा कहावत—“ बाबो बैठो ई घर में, और टांग पसारें ई घर में” अर्थात् बात कहीं भी हो रही है जबकि काम कहीं और है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने क्षेत्रीय अधिकारी महोदय से कहा कि सुनवाई के सम्बन्ध में प्रचार के लिए क्या प्रावधान है, तथा अपन लोगों ने किस प्रावधानों का उपयोग किया है, एक बार रामकुमार जी की बात का जवाब दें।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने जन सुनवाई के प्रोसिजर के बारे में जानकारी देते हुए बताना चाहा.....

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने पुनः बीच में बोलते हुए कहा कि सबसे पहले हमें ये बताइये कि आपने ब्लॉकों में नाम लिखे हैं हरिमा, सरासनी, डेह एवं भदामा जबकि ये मीटिंग जिन्दास गांव में क्यों? जमीन उन गांवों की, तो मीटिंग यहाँ क्यों?

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि आप द्वारा कहा गया कि सूचना नहीं थी, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार तीन दिन तक मुनादी करवाई गई थी, कि कहाँ पर ये जन सुनवाई है। जिसकी रेगुलर रिकॉर्डिंग भी है।


क्षेत्रीय अधिकारी
मानव संसाधन एवं ग्रामीण नियोजन मण्डल
राजीव (मानव संसाधन)


(मानव संसाधन)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजीव

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने पुनः बीच में बोलते हुए कहा कि मैं बताया हूँ, हर जगह हर चीज का होता है ये हुआ है। सार्वजनिक एक नोटिस भी होता है ना। आप वहां के लोगों की जमीन खरीद रहे हैं, जो गवाह बनता है उसका एक सम्बन्ध होता है, उसके घर पर नहीं मिलता है वो, टीपा-टापी नोटिस के आधार पर उसको अरेस्ट किया जाता है, आप तो किसी की जमीन हड़प रहे हो। भाई वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, एक चिपका दिया और फोटो खींच कर लेकर आ गये वो होना चाहिए आपका।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि ये जो जगह चुनी गई यहाँ जिसके पास साधन नहीं हो वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या, जिससे डेह, हरिमा, सरासरी या सरासरी से वहाँ पहुँच सकें। यहाँ वो ही लोग पहुँच रहे हैं, जिनको या तो कंपनी ने निमंत्रण दिया, या फिर जिनके पास खुद की गाड़िया है। किसान वर्ग के लोग साधन सीमित होते हैं, कम साधन है तथा यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सीमित है। आपको जगह चुनते समय ऐसी लोकेशन लेनी चाहिए, जहाँ सबका पहुँचना आसान हो। जिन-जिन गांवों में आपने मुनादी करवाई है, तो आपने गांवों की लोकेशन देखी है या कहीं किसी ने मना किया हो ऐसा हुआ है क्या? इसकी थोड़ी जानकारी देवे कि इस वजह से हमने ये लोकेशन चुनी है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि पब्लिक हियरिंग के लिए जगह साइट के पास अथवा उसी के ऊपर चुनी जाती है।

श्री कैलाश गौतम निवासी डेह ने कहा कि डेह बड़ी जगह है, उप-तहसील है तथा उसके लिए सब जगह के साधन उपलब्ध हैं। आप वहाँ करवा सकते हैं। गांव की युवाओं के साथ हम मैनेजमेंट व आपके लिए व्यवस्था भी कर देंगे। हमारे गांव क स्पोर्ट्स क्लब संचालक, गांव में किसान के हित के सार्वजनिक प्रोग्राम अथवा सरकार के प्रोग्राम में भी सहर्ष हम उनमें भाग लेते हैं तथा उन्हें पूरा भी करवाते हैं, अतः वहाँ हम आपका सहयोग भी करेंगे, लेकिन लोकेशन अथवा जो भी हो वो पहले से चिन्हित करें।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि आपके द्वारा जो बसें स्कूल की बसें मंगवाई गयी हैं, जो हरिमा व सरासनी से भी आई है, उसकी फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी है क्या? आपके स्वयं सहायता समूह जो महिलाएं बनी है उनके अलावा कोई एक भी आदमी उन बसों में नहीं था। जब आप राजनितिक उद्देश्य से बसें भेज रहे हैं तो उसकी विडियो क्यों करवायेंगे।

12-
क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य, राजस्थान, जयपुर
कमिशन (राजस्थान)

(सम्मेलन जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नामूर

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि जो मुनादी करवाई गई है, उसका फोटो यहां डिस्प्ले पर एक बार दिखाओं। कम्पनी का एक आदमी मेरे पास आ जाये, जो आपने मुनादी करवाई है, उसकी फोटो मेरे पास है, वो पढ़ कर सुना देवे।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि उपरिथत माता-बहनों जिन बसों में आप आये हैं, उनमें स्वयं सहायता समूह के अलावा कोई दूसरी सवारी थी या आप बताओ। ये आप सब को अनाथ कर रहे हैं, गाँ के घरने के काम घर में काम नहीं रहता, वैसे ही किसान की जमीन जाने के बाद उसके पास भी कुछ नहीं रहता।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पर्यावरणीय सलाहकार से कहा कि जो मुनादी की गई है, वो दिखाये। आप बताये कि आप लोगों ने क्या प्रचार किया है।

जन सुनवाई में पहुंची बस के ड्राइवर ने बताया कि मैं सरासनी एवं हरिमा से एक-एक बस लेकर आया हूँ, सरासनी से आई बस में 10 महिलाएँ तथा 2 जेन्ट्स थे एवं हरिमा से आई बस में 30-35 महिलाएँ तथा 2 जेन्ट्स थे।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि वह सभी महिलाएँ सहायता समूह वाली महिलाएँ जो कम्पनी में वर्क करती हैं, केवल वो ही थी, उसके अलावा कोई नहीं थी। इसका मतलब उन घरों में केवल इनके कामकाज था, गले की प्रकृति हो अथवा टेंपरेरी हो।

श्री शैतानराम ईनाणियां निवासी रूपासर ने कहा कि मैं भुगतभोगी हूँ तथा आज 17 महीने से मैं अंबुजा के खिलाफ धरने पर बैठा हूँ। हमारे साथ क्या हुआ, हमें क्या-क्या वादें किये, वो आप जरूर सुने। हमें पहले कहा गया था कि पुनर्वास, रोजगार देंगे, बच्चों को नौकरियां देंगे, परन्तु एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली, पुनर्वास नहीं मिला। विकास नाम की चीज विनाश करें। आसपास के जिन लोगों ने जमीन दी, उन्होंने तो दे दी, लेकिन उस जमीन के पास के जो खेत हैं, मकान हैं, उनमें दरारें आई हुई हैं। नराधना तक भी और ईनाणा के भी सभी होदों में दरारें आई हुई हैं। अतः ये जो डेह गांव है, इसमें आने वाले समय में झुंए के अलावा कुछ बसना नहीं है, ये पूरा गांव उजड़ जायेगा। आज मूण्डवा की ये हालात हैं यह जगह पर अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी मीणा जी से निवेदन है कि मूण्डवा की हालात देखते हुए फैक्ट्री को बंद करो। अगर इन्हें स्वीकृति देनी है तो पहले वहां प्रदूषण रोको। वहां जो हालत है वहीं हालत यहां होगी। आप 500-500

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

रुपये में भाड़ें के लोगों को यहां लाकर बिठा देते हैं और आप भाड़ें के लोगों की बात जन सुनवाई में भेज देते हो, तो यहां की जनता का क्या होगा। जब जमीन डेह, हरिमा एवं सशसनी की जा रही है, लेकिन आपने जन सुनवाई यहां रखी भी इसीलिए वही वहां की कोई वहां पहुंचे नहीं, जिससे आप चुपके से पर्यावरण की एनओसी ले लेंगे। ये खेल बहुत बुरा खेल है, जो जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। एडीएम साहब ये धाखाधड़ी आपके हाथ के नीचे हो रही है, हमारे साथ ऐसा न करो, इस धोखाधड़ी में आप शामिल हैं। या तो अंबुजा ने जो भी वादे किये वो पूरे करें, वहां वादे पूरे नहीं हो रहे हैं और आप यहां वादे कर रहे हो। यदि योग्यतानुसार नौकरी देने का कहते हैं तो मेरे तीन बेटे इंजिनियर एवं एक बेटी डॉक्टर हैं, मैंने एक नौकरी मागी थी, अंबुजा ने आजतक नहीं दी। यह सब झूठा दांसा है। जिन गाईनों की जमीन जा रही है, वहां जन सुनवाई नहीं करके मूल गांव में कर रहे हैं, इस गांव की जमीन नहीं जा रही है। छोटे-छोटे लालच से बच्चों को राजी कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। एडीएम साहब से निवेदन है कि आप लिखित में दो कि कितने दिनों में रोजगार दोगे, वह लिखित कोर्ट में भी काम आनी चाहिए। पहले भी नऊली नॉटेरी हमें दे दी कि जमीन की कीमत बढ़ाने पर आपको देंगे, पर वो कोर्ट में भी काम नहीं जाती। यह लिखित में भी जारी दे दें, यानि जनता के साथ अन्याय मत करो। आप समझदार हैं, फिर भी आपके हाने हुए ये धोखा कर रहे हैं, तो आप इनको रोको। जहां की जमीन जा रही है, वहां पर इस जन सुनवाई को वापस करवाएं, वहां की जनता की क्या समस्या हैं, उसे वा निवारण करवाएं तथा प्रदूषण बिल्कुल नहीं हो, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रदूषण को कैसे रोकेंगे और अगर कहते हैं कि यहां प्रदूषण नहीं होने देंगे तो पहले मुंखडा का प्रदूषण बंद करावो तब हमें विश्वास होगा कि वास्तव में यह प्रदूषण नहीं होने देंगे। मुंखडा की जो फैक्ट्री है वह बहुत धुआ देती है, पहले दिन में देती थी, फिर वैद्यरमैन सांतारामजी ने जनता को इकट्ठा करके विशेष बात की तब से दिन में धुआ छोड़ना बन्द करके रात में छोड़ना शुरू कर दिया। यहां आसपास की जनता पर आयेगी, ऐसे जनता को मत मारो। पहले मुंखडा फैक्ट्री का प्रदूषण बन्द करावो, तब विश्वास हो जायेगा कि यहां प्रदूषण नहीं होगा।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिभा ने कहा कि मैंने आधा घण्टा पहले बताया था कि डिस्प्ले पर ब्लॉक बता दीजिये, आधे घण्टे में जो आदमी एक ब्लॉक का निर्माण नहीं बता सकता, वो पर्यावरण के लिए क्या करेगा, क्या ही पेड़ लगा सकते हैं।

सुनील साहिब
अध्यक्ष जन सुनवाई विभाग
नगर निगम

(धर्मपाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि अभी डिस्प्ले पर दिखा देता हूं, बाकि प्रिंट करवाने के लिए हमने भेज दिया, सभी जगह वो ब्लॉक्स लग जायेंगे।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने कहा कि आर.जे. शाहप आप यह मान रहे हो ना कि यह बहुत बड़ी गलती है, तब तो इस स्थिति को कसी एक पक्ष और नई तारीख दो। इतने बड़े उद्योग समूह द्वारा इतनी बड़ी नेगजीलेंसी किंग जाना, वो भी दोनों-तीनों अधिकारियों की मौजूदगी में, ये कितनी बड़ी नेगजीलेंसी की बात है। आप कह रहे हो लगा देंगे, अब लगाने से क्या फायदा? इन बातों की बात सही है, कि प्रत्येक खातेदार को यह पता होना चाहिए कि इस खातेदार का खेत, यह उस ब्लॉक में आ रहा है, उसे क्या आपत्ति है जो वहां आकर खेत करता, अभी तक किसी को पता ही नहीं है। आपका दायित्व ये था कि इस पंचायत समिति के प्रधान, यहां आसपास के तमाम जनप्रतिनिधि उनको इस जनसुनवाई की सूचना व्यक्तिगत रूप से भी होनी चाहिए। क्योंकि आपने तीनों पत्र अलग-अलग अखबारों में अलग-अलग प्रकाशन दे दिये। पता ही नहीं है कि सी1 का कब है, सी2 का कब है, डी1 का कब है। जैसे हमने एक अखबार में पढ़ा, कि यह जरूरी है कि सभी नव भारत टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। द इंडियन एक्सप्रेस जयपुर में भी दूसरे दिन आता है, तो मुझे नहीं लगता कि नागौर में किसी ने ये पढ़ा भी हो। एक दे दिया दैनिक नवज्योति में, जिस अखबार की तीन प्रतियां नागौर जिले में नहीं आती, उसके अन्दर छाप कर आप पत्र सुवर्णाई करना शुरू हो, तो हमें भी गत बुलाओ आप। अभी राजोवीरा की सुनवाई चल रही थी, तो हमें रोजगार मिलेगा। पूर्वजों की कहावत कहते हुए कहा कि "बड़ा घरा में के परनाई, और मिलन रा आसां"। थोड़े दिन रुक जाओ आप, रोजगार ऐसा मिले आपको, अभी अखबारों में राजा रघुवंशी एवं सोनम की कहानी देखता हो या नहीं, जिस दिन शादी हुई उस दिन राजा रघुवंशी भी बहुत खुश हो रहा था, लेकिन एक किलोमीटर दूर ले जाकर खाई में डाल दिया। आपकी यही लाज है जो एस.एम.एस. कम्पनी करेगी। अभी कुछ दिन खुश हो जाओ, जो आपको सौखा कर लाये है ना, और अखबारों में पढ़कर भाषण लिख कर लाये है, ये पढ़ लो, लेकिन ध्यान रखना यहां रोजगार करेंगे कब, फेंफड़े तो सबके खराब हो जायेंगे, अपन तो टीवी हॉस्पिटल एवं भदानी के बीच में ही बसों में घुमेंगे। जब रोजगार की बात कर रहे है तो मुण्डवा मे देख लो, यदि किसी के पास आई-फोन है तो वह इसके जरूर एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्वाआई) चेक कर लेवे। यहां बैठे सभी अधिकारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन ये बोल नहीं सकते, क्योंकि जन सुनवाई बहुत बुरा व्यवस्था कर रहे है, इन सब पर नजर है, कौन पब्लिक के पक्ष में बोले, सुनते

अधीक्षक
जनसुनवाई एवं प्रशिक्षण निदेशन मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(सुपरीवाइजर के पद पर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

अखबार में पदस्थापन की खबर आ जायेगी। जिनसे आप लड़ रहे हो वो कोई छोट लोग नहीं है। यहां सबसे पहले जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी के लिए जो व्यक्ति आये या रेनड जी सीपी के जो व्यक्ति 2017 से इस क्षेत्र में आ गये, हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा विकास करेंगे। जब आज मैंने सोशल मीडिया पर 11:00 बजे पिन्टो में जन सुनवाई में उपस्थित रहने की पोस्ट की, तो 10:55 बजे इनका मैसेज आया। मैं हमसे क्या-क्या चाहते हैं और आप इनसे क्या उम्मीद लगा कर बैठे हो, कम-से-कम आपको ज्ञान तो होना चाहिए। आज आप हाथ काट कर इन्हें दे देंगे तो फिर आप सरपंच, प्रधान या एमएलए के पास किस उम्मीद से जायेंगे, वो भी क्या कर सकेंगे। सैनी जी ने मैसेज में भदाना को भाड़ण लिखा है, जो व्यक्ति 2017 से यहां रह रहा है, वो इंसान भदाना को भाड़ण लिख सकता है, तो थोड़े दिनों बाद भदाना को विधवा भी लिख सकता है, इन्हें कौन मना कर सकता है। हम सब मरे नहीं हैं जो विधवा लिख देंगे। माननीय कलेक्टर साहब के आदेश 183 का हवाला देकर तथा किसी को सूचना नहीं की गई, किसका खेत आ रहा है। तथा आप कह रहे हैं कि हमने मुनादी करवाई, मुनादी के भी सारे कांटोपामास पास हैं, इन्होंने एक पिकअप के ऊपर एक पर्दा लगाया है, एक-एक गांव में पिकअप को थोड़े से समय के लिए भेजी है, हो सकता है कि वह पिकअप पाला में से लेने गया हो, उसके पर्दा लगा दिया, जिसके अन्दर लिखा है "प्रस्तावित उर्जा मुना पत्थर ब्लॉक, ऑक्जान ब्लॉक की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु, प्रस्तावक गैसर्स सी. एस.डब्ल्यू. सीमेन्ट लिमिटेड, खनन पट्टा क्षेत्र 357.0937 हेक्टेयर की जन सुनवाई दिनांक 12 जून 2025 दोपहर 1 बजे, स्थान- राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिमरन संख्या 2 में आयोजित होगी।" आप हमें अभी भी अंधेरे में रख रहे हो, अलग-अलग अखबारों में तीन दिन सूचना देना, किसी जन प्रतिनिधि को सूचित नहीं करना, यथा उनकी इच्छा और जगह नहीं बनती कि कम से कम यहां के जन प्रतिनिधि प्रधान सरपंच आदि को सूचना करें। संविधान के आर्टिकल 12 एवं 21 महत्वपूर्ण शक्ति है, उसमें हमें स्वच्छ फोंफड़े, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण के प्रति हम सब की ज़िम्मेदारी है, जो अधिकारी बैठे हैं आपकी भी। हमारे जो भूल कतब्य हैं, उसको बहुत हमें क्या-क्या करना चाहिए। आज लाखों पेड़ ये उखाड़ देंगे। 2017 से अब तक तो यह बात है कि ग्रीन कॉरिडोर, आठ साल बाद आप ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हो। आप यह भी स्पष्ट कर दें कि देश कानून से चलाना चाहते हैं या डंडे के जोर से चलाना चाहते हैं और अगर आपका यह है कि डंडे के जोर से देश चलायेंगे तो आप अपना रास्ता तैयार करो और हमारी बाजुओं में दम होगा तो हम अलग रास्ता तैयार कर लेंगे। जे.एस.डब्ल्यू. को ऐसे ही लोगों को लूटने लेंगे।

सचिव, जन सुनवाई
राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिमरन संख्या 2

(समयांतरित सीनियर)
जिला कलेक्टर
जयपुर

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवसर ने एडीएम साहव को संबोधित करते हुए कहा कि 10 किलोमीटर रेडियस के अन्दर जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी ने केवल 8

बताव बताये हैं, आप सभी ने भी पढ़ी होगी, जब आप यहां न्याय करने आते हैं और यह कह रहे हैं कि एक महीना पहले आपने विभिन्न स्थानों पर— पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर, सूचना केन्द्र, आरओ ऑफिस तथा और भी स्थानों पर इसका सारा लिटरेचर उपलब्ध है, तो आपने भी इसका अध्ययन कर लिया होगा और जब एक तरफ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने 22 अप्रैल 2025 के पत्र में हमारे सांसद हनुमान बेनिवाल जी को संबोधित करते हुए लिखा है " कृपया अपने द्वारा दिनांक 28/03/2025 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाये गये विषय का संतर्पण करें, जिसमें आपने राजस्थान की दो सीमेंट कम्पनियां नामतः अंबुजा सीमेंट, जिला नागौर और जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट, सरासनी जिला नागौर के द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित शर्तों की अनुपालना रिपोर्टों का भौतिक सत्यापन करने की मांग की थी, मामले की खास उपरान्त जयपुर स्थित मंत्रालय के अधिनरथ कार्यालय का अनुदेश दिया गया है कि वह शीघ्र उठाये गये मुद्दे के संबंध में यथाशीघ्र स्थल निरीक्षण कर तथ्यात्मक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि मंत्रालय द्वारा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।" क्या आप मंत्री से बड़े हो गये, जब मंत्री ये कह रहे हैं कि भौतिक सत्यापन करने के बाद पर्यावरण स्वीकृति आप दे सकते हो। सामान्य सांसद का 377 के तहत, मुझे लगता नहीं कि आप कभी एनए एवं एनएसए के एम्पिलेज विशेष अधिकार हानन के, उसमें आप फर्सें नहीं करे आईएस, आईपीएसों की लाइन लगती है, बाहर बेंच पर बिठाते हैं, कलेक्टर, एसपी और डीजी को, यदि यह जन सुनवाई आपने इस आदेश का उल्लंघन करने का जरूरत की हो हम आपको लोकसभा की कार्यवाही तक में, माननीय सांसद को इस से अपमान करने वाला हो फिर संसद और देश का कानून कुछ बचता नहीं, मंत्री से बड़ा आरओ एवं एडीएम हो गये। आपके जो मन में आयेगा वो आप दोगे। उन्होंने भौतिक सत्यापन कर लिया क्या, भौतिक सत्यापन के बिना रोक लगाई गई है, चिन्ती आपके पास भी आई होगी। इसके अलावा 10 किलोमीटर की परिधि के अन्दर आपने सिर्फ पांच तालाब बताये। जो आंकड़े में आपके सामने प्रस्तुत हैं, यह 10.26 लेण्ड रेवेन्यू के रिकॉर्ड है, डेह का तालाब तहसील का कार्यालय में जमाबंदी के आधार पर खसरा नं. 1421— गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 1475— गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 183— गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 192— गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 202— गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 439— गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 537— गैर मुमकिन नाड़ी ये केवल डेह का, भदानी का खसरा नं. 184— गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 461— गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं.

सांसद अनिलकुमार
 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 नागौर (राजस्थान)

(सत्यापन केन्द्र)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 नागौर

501- गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 606- गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 660- गैर मुमकिन नाड़ी तथा सरासनी में खसरा नं. 295- गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 41- गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 72- गैर मुमकिन नाड़ी एवं हरिमा के तालाब में खसरा नं. 500- गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 547- गैर मुमकिन नाड़ी तथा जिन्दास जहाँ ये जन सुनवाई हो रही है में खसरा नं. 214- गैर मुमकिन नाड़ी, खसरा नं. 81- गैर मुमकिन नाड़ी इस प्रकार कम से कम 35 तालाब है, छोटे नाड़ों की अगर बात करे तो, लगता है शहर में आकर आप लोग भूल गये हो, नाड़ा की नाड़ी जितना ही महत्वपूर्ण है गांव वालों के लिए, जो द्वाणियों के अन्दर रहते हैं जो 10 किलोमीटर गांव थोड़े जाते हैं, वो छोटे नाड़ों से अपनी न्यास बुझाते हैं, उनमें कहीं इसमें जिक्र नहीं हैं। जिसने भी यह रिपोर्ट बनाई, मुझे या ईसा लगता है कि उन्होंने नागौर नाम देख लिया है तो ना-गौर, कोई गौर करने वाला नहीं, ना-गौर यही होता आया है, लेकिन अब ध्यान रखना नागौर ना-गौर नहीं रहा, अब सब लोग गौर करने लगे हैं। इसके अन्दर जितना बड़ा झूठ का पुलिन्दा तैयार किया है उस पुलिन्दे का आप लोग भी एक बार अध्ययन करो। यहाँ उद्घाटन विभाग के अधिकारी, कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि एडीएम साहब तथा तहसीलदार जी मौजूद हैं, आप लोग एक किसान के 91 में दर्ज करके उसको जेल में एक मिनट में जमाने देते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका दूसरा इन्टरैस्ट होता है, अब करो कार्यवाही, इतना बड़ा आपका दिल है और आप जो सोचते हो मजिस्ट्रेट की पॉवर है मेरे पास, तो आज मजिस्ट्रेट की पॉवर का इस्तेमाल कर लो, जिससे आपको भी पता चल जायेगा कि मजिस्ट्रेट की पॉवर सिर्फ गरीब लोगों का तंग करने के लिए ही नहीं है या कानून में, बाबा साहब ने कहा प्रत्येक व्यक्ति समान है, समान कहें, बताओ। गांव का एक गरीब व्यक्ति यदि धोरा इधर-उधर कर दे तो तहसीलदार जी उसको सिविल कारावास की सजा कर दे। यहाँ तो इन्होंने भित्तना बड़ा झूठ बोला है, आप चाहे तो इसका अध्ययन करके जे.एस.डब्ल्यू. को लोगों को, जिन्होंने बनाया है, अन्दर डालो। अभी तो सिर्फ तीन ब्लॉक की जन सुनवाई हुई है, शायद एक ब्लॉक की इन्होंने पहले कर ली, तो चार ब्लॉक इस इलाके में- सरासनी, हरिमा, भदाना और डेह का, अभी तो इनको पता लगा कि यहाँ सारे जमीन के नीचे लाईमस्टोन है, धीरे-धीरे सबका नम्बर आयेगा। अभी काफी लोग भोला-भाला हैं, उनको धीरे से कान में बोल दिया कि तुम्हारी एक जेसीवी लगा दूंगा और तुम्हारे डम्पर तैयार, एनजीओ वालों को बोल दिया कि दिवारों पर नारे लिखने का काम तुम्हें ही दूंगा, किसी को बोल दिया कि तुम्हें पेड़-पौधे लगाने को दूंगा। हम लोग यहाँ अपने भाईयों को मार कर, किसके दिवारों पर नारे लिखोगे, थोड़ा बड़ा

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर अधिकारी

मुख्य न्यायाधीश, जिला न्यायालय
जिला न्यायालय, जिला न्यायालय

हस्ताक्षर
(मुख्य न्यायाधीश, जिला न्यायालय)
मुख्य न्यायाधीश, जिला न्यायालय

रखा। इस वचन में कहानी सुना करते कि 'एक आदमी के पास एक तोता, एक मुर्गा, एक बकरा एवं एक पांडा था, जब वो बिमार पड़ा तो वैद्य जी ने सब देख कर कहा कि इसे तोता को उबाल कर उसका सूप पिलाएं तो यह तैयार हो जायेगा, तोते को पता चल गया कि मुझे मारेंगे तो वो अपने तीनों साथियों को आगे रोया कि मैं तुम्हारे साथ रहा हमेशा मुझे बचाओ कैसे भी। पर उन तीनों ने ध्यान नहीं दिया, वे चले गए और दिया तथा सूप पीकर वो ठीक हो गया, जब ठीक हुआ तो परिवार वाले मिलने आये और कहा कि वैद्य जी ने निहाल कर दिया, अब काँटें करते हैं, पार्टी के लिए मुर्गा काटा जाये, तब मुर्गे को काटा, बाद में ज्यादा लोग आये तो ज्यादा भीड़ हुई तो कहा बकरे को काटो, तब बकरे को काटा गया, अब आसपास पता चला कि वैद्य जी मरणासन आदमी को ठीक कर दिया तो ज्यादा लोग आये, सब कहा कि अब पांडा के बिना काम नहीं चलेगा, तो उस पांडा को काटा गया।' मतलब यही है कि नम्बर सभी का आयेगा, ध्यान रखना। ये बातें हरिमा, सरासनी तक ही नहीं छोड़ेंगे, ईधर नीचे झाड़िसरा तक ये देख लेंगे। नीचे तेल है, गैस है, कोयला है या लाईमस्टोन क्या है। सबको मारेंगे, यह मत सोचना कि आज तो इनका है तो हम तो ताली बजा ले और जे.एस.डब्ल्यू. के पक्ष में बोल लेंगे, ऐसा अफसोस नहीं करना। शुरुआत में मूण्डवा में जन सुनवाई हुई, मैं भी गया था, आज कहा वे शरारत जी और बैठे हैं ना, इन लोगों को मैंने बहुत बातें बताई परन्तु इन्हें समझ नहीं आई, काफी लोगों को नहीं समझ आई। कुछ ने कहा हमें डम्पर लगा लेंगे, अब उन्होंने क्या किया है, रेल भी सीधी अन्दर लेकर आते हैं, डम्पर और जे.सी.वी. सबके घर ही पड़े हैं, अब रेल भी अन्दर लाते हैं तथा जो पत्थर खनार से आता था, वो सीधा कन्वेयर बेल्ट से आता है। आपके यहां भी कुछ खुश हो रहे हैं ना, शायद आप लोगों को पता नहीं है कन्वेयर बेल्ट की भूमि भी आवाप्त हो गई है, एक-दो खेत को छोड़ कर। पत्थर क्रेशर से टूटेगा और सीधा फैक्ट्री में आयेगा। राजीविका वाले बाईजी जो बोल रहे थे ना, आपको यहां अन्दर जाने नहीं देंगे ये, मूण्डवा वाले अभी अंबुजा में जाने की कोशिश की परन्तु इनसे मिलते ही नहीं हैं। अकिड़ा के हिसाब से मिलाते 2 साल से मूण्डवा तथा ईनाणा के सभी तालाब खाली पड़े हैं। वरशात चारों तरफ हुई परन्तु मूण्डवा, ईनाणा में नहीं हुई। मैं उद्योगों के खिलाफ नहीं हूं, आप लगाओ, रोजगार दो कौन मना कर रहा है, परन्तु अपने को मार देंगे, लोगों के फेंफड़े खराब कर देंगे, तो रोजगार किसके पास आयेगा। उसी ब्लॉक में सैकड़ों खेत कम्पनी लेंगे परन्तु रोजगार केवल 91 लोगों को देंगे, वो भी यहां एक भी उस योग्यता वाले नहीं है, वो होंगे गार्डिन्स मैनेजर, गार्डिन्स मेट, प्लान्टर, खेतार आदि तथा जो ड्रिलिंग का काम करते हैं ना उन्हें देंगे।

अपने को रोजगार की बात नहीं लिख रहे हैं। यदि अपने खेत छिन लेंगे तो बाहर पर हजारों लोग तो बेरोजगार हो गये। कोई तो बोलते हैं कि कहीं और जमीन मिले लेंगे, लेंगे कहां से बताओ। आपने यहां 8 लाख में जमीन बेची और हमारे गांव उस समय 3 लाख में आती, अब कहते हैं कि भदाना में 8 हो गई तो 6 तो हमारे भी हो। आप सभी एक-एक चीज पर मंथन करो और आने वाली पीढ़ी का साधन बना। कोई तो कह दे कि मैं तो 8 लाख से रुपये लेकर फॉर्च्युनर लेकर आऊ, बढ़िया घर बना लुंगा, लेकिन घर एवं फॉर्च्युनर से काम नहीं चलता। सना एक लाख रुपये पहुंचा, लुगाई (बीवी) कौन लायेगा, इस क्षेत्र में बहुत लोग कुंवारे गुम रहे। विकास की बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की कि इन्होंने विकास कर दिया, मैंने आंकड़ा लेकर आया हूं, इस पर आप सब गौर करना। इस फैक्ट्री के लगने से पूर्व 2018 से पूर्व यहां डेह कि जो शराब की दुकान है, यहां हरिमा और फैंक्ट्री के सामने भी एक दुकान है और भदाना फांटा पर भी, इन सब दुकानों को मिलाकर 15 करोड़ की शराब, दारू एक साल में बेचा जाता है, जो पहले केवल 4 करोड़ का काम चला था, ये विकास बहुत अच्छा 4 गुणा कर दिया। यहां अपराध ऐसा कम है कि अभी तो यहां बिहारी तथा बंगाली आते हैं, ये बोलते क्या हैं यहीं पता नहीं चलता। यहां भदाना, जिन्दास के लोग नौकरी करेंगे तो कर्म हम आ भी जायेंगे, पता तो चलेगा, आप बात तो बताओगे, वो लोग तो क्या बोलते हैं पता नहीं चलता, बिहारी एवं बंगाली गालियां निकालते हैं या प्रशंसा करते हैं कुछ पता नहीं चलता। आपको यहां रोजगार कि जो झूठी बातें कर रहे हैं, किसी आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। यह रही अंबुजा सीमेंट, पहले एक बार जाकर भ्रमण करके देख लें कि कितने लोकल लोगों को रोजगार मिला है। इन्होंने उरीन की बात कही, उरीन इसमें भी है, 5 की जगह 40 से ज्यादा है। अभी 5 जून को ही पर्यावरण दिवस की बात कर रहे थे, लोगों ने मनाया, अभी हमारे प्रधानमंत्रीजी और मुख्यमंत्री जी दुधरी गंगे आदि में तगारी और पावड़ा आदि से तालाब खोद रहे हैं, एक तरफ तो तालाब खोद रहे हैं तथा दूसरी तरफ इन 40 को हम उजाड़ रहे हैं। हम काम क्या कर रहे चाहते हैं कम से कम ये पता तो चलें। वास्तव में नियत क्या है, लोगों के स्वास्थ्य की नियत है या प्रदूषण से बढ़िया जकड़ कर ईलाज करने की नियत है। इन दोनों से विस्तृत रिपोर्ट लेनी है। दूसरी बात इन्होंने जो इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो क्रेशर लगेगा, 1600 टन प्रति घण्टा। अभी कोई अध्यापक बता रहे थे कि जे.एन. डब्ल्यू ने हमारे बहुत विकास किया, तो बताइये क्या विकास दिया, जब लौकिक वच्य ही 250 है, तो क्या यहां कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना रही। अभी वच्य 250 है, तो साल बाद देखना यहां 50 भी मिल जाये तो। यहां भुण्डवा बगे तथा और क


श्री. जे. न. डबि
 अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 गरीब (गजराया)


(चम्पालाजीनगर)
 अतिरिक्त शिक्षा प्रशासक

स्कूलें बन्द हो गई हैं। हम आगे बात वहीं करें जिसमें सत्यता हो। अभी फैक्ट्री बना नहीं, बनने के बाद पर्यावरण, फोंफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब सब चीज गई आगे जमी है लेकिन फोंफड़े नहीं आये हैं। फोंफड़े खराब होने पर आदमी मरता ही है और फोंफड़े खराब करने की जगहमें बड़ी फैक्ट्रियां आपके आसपास लग रही हैं। सीएसआर फण्ड को भुगत कर रहे हैं, कि इसके तहत क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। 2 प्रतिशत सीएसआर फण्ड लोकल जगह पर खर्च होना, लेकिन अंबुजा का सीएसआर फण्ड वो जयपुर के अन्दर खर्च हुआ है। आप आंकड़ें देख सकते हैं लोकल इलाक़ों में बिल्कुल खर्च नहीं करते।

जल की आवश्यकता 200 किलोलीटर प्रतिदिन भूजल एवं खदान दोनों को लिए, बिजली आवश्यक 20 मेगावाट तथा श्रमशक्ति की आवश्यकता 91। खनन पर विवरण पूर्ण यांत्रिकृत ओपन कास्ट खनन एवं खनन की आयु 119 वर्ष बताई है और अंतिम कार्यशील गहराई 40 मीटर अर्थात् लगभग 120 फीट बताई है। प्रतिदिन 2 शिफ्ट में गजदूर एवं वर्मचारी 12 घण्टे काम करेंगे, जबकि 8 घण्टे से अधिक काम करना भद्रपुर के अधिकारों का हनन है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी आपने बताया है कि यहाँ से कुछ खदान नहीं है, खनन उत्पादन 140 मिलियन टन तथा ये जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्रेशर गांव से 150 मीटर दूर, यहाँ तहसीलदार जी बैठे हैं अपने भू-राजस्व के जो कानून है वो ये कहते हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर ग्रामीण आबादी के अंतिम छोर से उद्योग नहीं लगा सकते। अब ये 150 मीटर पर क्रेशर लगाने की बात कर रहे हैं तथा उस क्रेशर की क्षमता 1600 टन प्रति घण्टा, अर्थात् क्रेशर उत्पादन 1600 टन प्रति घण्टा यांत्रिकृत ओपन कास्ट विधि से परिवहन के लिए 40 डम्पर भी आवश्यकता है। अब अगर 16 घण्टे काम करेंगे तो 640 डम्पर कोवल एक क्रेशर पर चलेंगे। अब इस इलाके से 640 डम्पर गुजरेंगे तो यातायात पुलिस वालों से भी राय ले इस बारे में कि जब 640 डम्पर कच्चे रास्ते से निकलेंगे एवं आसपास के इलाके के लोगों की क्या हालात होगी। इनके बारे में भी हमारी में कुछ लिखा है। खनिज परिवहन 40 टन डम्पर्स द्वारा 1600 टन प्रति घण्टा अर्थात् 25600 टन 640 डम्पर पर ट्रिप होंगे, 640 ट्रिप में डीजल, डम्पर परिवहन लोडिंग मशीन, जो 200 लीटर प्रति घण्टा खपत करेंगे, संख्या 5 हो गई है। 5 गैकलेन से 40 डम्पर भरेंगे। अब इनके कार्बनडाई ऑक्साइड एवं CO गैस का जो उत्पादन होगा, जिससे वायुमण्डल में आसपास में स्थित गांवों, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग भी निकल रहा है सोनी भाईन्स के अन्दर से, में बिमारियां उत्पन्न होगी साथ ही 1600 टीपीएच क्रेशर से डस्ट का उत्पादन होगा, उस रोकने के लिए क्या क्या उपाय किये बताएँ। इन्होंने लिखा कि वेट ड्रिलिंग करेंगे, मैं स्वयं भी खान

बिना अक्षर

(अक्षर)

(अक्षर)
अतिरिक्त जिला सहायक
कनौर

मायसाय से जुड़ा हूं तो टेक्नीकली कुछ जानता हूं, अभी तक बाहर से उस पर
 जरूर बेट, गीला कर सकते हो, लेकिन जो ड्रीलिंग की बड़ी मशीनों से धुआं निकल
 उड़ता है। एडीएम साहब हो शायद आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते।
 क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में हो तथा कोई एक आयपी हम क्षेत्र में प्रफेक्ट कर
 हो सकता, इस जन सुनवाई को स्थगित करके, एक बार आप जो भी बड़ी सीमांत
 पी फैक्ट्रियां हैं, उनके ड्रीलिंग सिस्टम को देखो और फिर अगर लगे कि यह ठीक
 ड्रीलिंग कर लेंगे, धुआं, धूल नहीं उड़ने देंगे, एक महीने बाद वापस इस जन
 सुनवाई का आयोजन करके फिर एनओसी दे देंगे। आप जो नगर विन्डुअर
 आप ध्यान रखें। कम्पनी ने नगर परिषद नागौर से एमओयू किया है, जिसके हिस्से
 नागौर से लेकर यहां तक पाईप डाल दिये गये हैं। नागौर से आपको पानी दो
 फौन, नागौर में विगत 3 माह से की हालत यह है कि ताले लगे हुए हैं, कभी
 अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, कोई सड़क का कह रहे हैं, तबसे लोगों ने नागौर
 अन्दर सड़क नहीं बनाई, पानी नहीं पिलाया, जो आपको यहाँ से गुजरकर बाहर
 200 किलोलोटर पानी दें देंगे। केवल ओकड़ों को मत देखा, ये भी देखा
 प्रेक्टिकली ये चीज संभव है या नहीं, इन सब चीजों पर भी हमें अध्ययन करने का
 बहुत जरूरत है। इसके अलावा उत्खनन का जो विवरण है, इसके अन्दर समाप्त
 उन्होंने किया नहीं, इसके अन्दर भी खूब झुंठी बात लिख कर दियायेंगी करने का
 काम किया है। संभावित पर्यावरणीय प्रभाव तथा नवीनीकरण उपाय प्रोत्साहन पाने का
 साथ बताया गया है, ये गलत है, क्योंकि कम्पनी हेवि-अर्थ माइ से ड्रीलिंग करती है
 उस ड्रीलिंग से पानी का प्रावधान है ही नहीं, दैनिक उत्पादन 25600 टन उत्पन्न
 प्रतिदिन कितनी ड्रीलिंग होगी, उस ड्रीलिंग में कितना पानी आयेगा, ब्लास्टिंग से
 पश्चात पानी छिड़का जायेगा या नहीं, उसका विवरण भी नहीं दिया है। जिस से
 पर डम्पर चलेंगे, उस पर पानी छिड़कावा की क्या व्यवस्था है, उसका भी विवरण
 नहीं दिया। हेवी ब्लास्टिंग से जो नाइट्रोजन व सल्फेट फ्यूमस उड़ेंगे, आसपास
 जन मानस को प्रभावित करेगी, इसको रोकने के क्या उपाय हैं, इसका भी विवरण
 स्पष्ट नहीं दिया। खान का क्षेत्र 300 हेक्टेयर से भी बड़ा है, जो वर्षा का कैचमेंट
 क्षेत्र भी है, क्योंकि इसके अन्दर भी नाड़ियां हैं। माननीय उच्च न्यायालय में अब
 रहमान प्रकरण से आज पूरा राजस्थान के बड़े-बड़े उद्योग ठप पड़े हैं, आप रेपरीट
 करके आप सभी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, न्यायालय में कितने प्रकरण आ रहे हैं
 कि कैचमेंट एरिया में अगर किसी का उद्योग अथवा घर आ रहा है तो उस पर
 बुलडोजर चलाओ। एक तरफ आप उधर बुलडोजर चला रहे हो, दूसरी तरफ कह
 रहे हो कि कैचमेंट एरिया में आप माईनिंग करो, दो तरह का कानून देश में लगे

राजाजी अधिकारी
 जनसुनवाई एवं प्रशिक्षण निदेशक, राजस्थान
 नागौर (राजस्थान)

(व्यवसायिक निदेशक)
 अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान
 नागौर

चलेगा, इस पर भी आप पूरा लिखित में लेवें। इन्होंने लिखा है कि इस योजना अवधि के दौरान कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा, जो पूर्णरूप से गलत है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी नागरिक का हवा, पानी, रोशनी कोई व्यक्ति अथवा संस्था अपने व्यापार के लिए बाधित नहीं कर सकता। ये हमें हमारे संविधान की जो आत्मा है, जिसके बंदोलत हम जिन्दा हैं, उसके अन्दर आते हैं। 21 यह कह रहा है कि हमें शुद्ध वायु एवं शुद्ध पानी के लिए हम हकदार हैं। माईनिंग प्लान की बात है, इन्होंने ये रिपोर्ट दे दी, बता रहे हैं कलेक्टर ऑफिस, राम पंचायत और भी अन्य जगहों पर रखी है। अगर सरपंच साहब ये कहें कि इन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है और यह सही है, तो आप इन्हें एनओसी दे दो। एक प्रोजेक्ट व्यक्ति को इस 800 पेज की रिपोर्ट को नहीं पढ़ सकता, इसमें कंजुश इंग्लिश लिखी है। इन सब चीजों को आप स्थानीय भाषा में शुद्ध हिन्दी में अनुवाद करवाकर लोगों को वितरण करें। इन्होंने लिखा है कि हम यहां भू-जल का दोहन नहीं करेंगे तथा सीजीडब्ल्यू की परमिशन के बिना आप कर ही नहीं सकते। यहां के सभी ब्लॉक टीने-धीरे-धीरे जॉन की श्रेणी में आ गये। अभी कितनों में तो 50 बता रहे हैं कि हम पानी यहां से ले आयेंगे, यहां एक ट्यूबवेल भी नहीं खोदेंगे, क्या यह सम्भव है? ये अपनी फैक्ट्री एरिया तथा माईनिंग एरिया में ट्यूबवेल्स खोदेंगे इस क्षेत्र का सारा पानी दोहन कर लिया तो यहां के लोग तो पलायन करने पर मजबूर हो जायेंगे। अब फैक्ट्री लगभग बनकर तैयार है, परन्तु 2017 से अब तक कितना ग्रीन गैरड बनाया। ये तीनों ब्लॉक लगभग एक ही इलाके में एडजस्टमेंट की भाषा में हैं। उसके अन्दर यदि हम खसरों को बात करें, तो हजारों किसानों को आप जमीनें लेंगे, एक पेड़ औसतन एक लाख लीटर प्रति वर्ष ऑक्सीजन देता है अर्थात् प्रतिदिन 264 लीटर ऑक्सीजन एक पेड़ दे रहा है तथा एक व्यक्ति की दैनिक जरूरत 550 लीटर है, अर्थात् उसकी आधी है। यदि एक आदमी को जिन्दा रखना है, तो दो पेड़ कम-से-कम चाहिए ये विज्ञान कहता है। आप यहां लाखों पेड़ काटेंगे, जिसका मतलब आपने लाखों लोगों को मार दिया। आपके पेड़ जब जवान होंगे। जब जोधपुर-नार्गौर हाईवे बना, इनके अन्दर खूब पेड़ काटे, जिस कंपनी ने हाईवे बनाया, उसने अधिकारियों को भी लिखित में दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नार्गौर से लेकर जोधपुर तक किसी ने कोई बड़ा छायादार पेड़ नहीं है। तो क्यों जे.एस.डब्ल्यू एक ही दिन में लाखों पेड़ लगा लेगी? इससे अच्छा तो यह हो कि आप यहां हरिमा में चारों तरफ फोर्स लगा कर बीस-तीस जलाद लाओं और भार दो सभी को, आज जैसे फोर्स लगाते हो ना। सरासरी एवं जिन्दास का नाम आते ही पुलिस के कुछ अफसरों को बहुत मजा आता है, यही

24
अधीनस्थ अधिकारी

जयपुर जिला, जयपुर जिला, जयपुर जिला
जयपुर (जयपुर)

1
(धर्मालाल जीनवर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नार्गौर

वहां ठोकेंगे। गरीबों को ठोकने से क्या होगा? आप लोग गरीबों को डंडे से मार कर स्वर्ग में नहीं जाओगे। अगर आपको वाकई डंडे मारने का शौक है और लगता है कि वर्दी में दम है तो जे.एस.डब्ल्यू. वातो मार रहे हैं ना लोगों को, करो इन्फैंट्रिलेज। ताकि आप लोगों को भी पता चल जायेगा। अब भाई लोगों का छोड़कर सब को एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप भी किसान परिवार के लोग हैं। कई बार कोई आदमी आपको भगवान मानते हैं, हम भी तिरंगे को मानते हैं, आज तिरंगा लगा है वहां पहले बुजुर्ग लोग जुते खोल कर निकलते थे, आज भी श्रद्धा हमारा भी सर झुकता है, हम ये सोचते हैं कि अन्दर कोई न्याय की मूर्ति बैठी है, लेकिन जब ये गरीब जे.एस.डब्ल्यू. के खिलाफ आपको ऑफिस आते हैं तो कार्रवाई पर आंखें निकालते हो, तो आपके बच्चे सक्सेज नहीं होंगे। इन इंचार्ज को पिता और पानी पिलाओ, किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो। इस फैक्कड़ आने के कारण नशा प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ी है। एडीएम साहब आप एक बड़ा आंकड़े भी ले लो कि मूण्डवा की शराब की दुकानें अंगुजा के लगाने से पहले कितनी शराब बँचती थी, अब 6 गुणा या 7 गुणा बेचती है तथा देह भक्षणा की दुकानें हैं, ये भी दारु कितना गुणा बेचते हैं। इन चीजों का मतलब क्या कर लो, हम देखेंगे कितना विकास हुआ है। जब शराब की बात की तो इन्वर बैठी यहाँ पर सर हिलाया, इसका मतलब किसी का भाई, पति, रिश्तेदार नशा करता है, दुसरे सभी को है, पर कर क्या सकते हैं। यहां बाहर से आदमी को साथ नये-नये लोग लेकर आ गये। इन सब बातों पर भी ध्यान रखते हुए, मैं आगस व्यक्तिगत रूप से करूंगा कि आज की जन सुनवाईयों को, क्योंकि एक तो लोगों का समय पर सुनवाई नहीं हुई, अलग-अलग अखबारों में दिये, कहीं मुनादो आप कर नहीं पाये, पूरे देश में माननीय कलेक्टर ने धारा 163 लगा रखी है, जिससे लोग शादियों में जान डरने लगे, यहां भी लोग आये नहीं, वरना इतने लोग आते कि ये पाण्डाल बन पड़ता। हम उद्योगों के खिलाफ नहीं हैं, जब देश के प्रधानमंत्री तथा जे.ए.इ.कोनोमिस्ट ये कह रहे हैं कि उद्योग लगा कर देश आगे बढ़ाओ, तो हम भी कह रहे हैं लगाओ उद्योग, परन्तु किसी को मार कर, किसी को काग़ खोदकर पानी ऊपर से रास्ता निकालोगें तो मैं उस उद्योग के पक्ष में नहीं हूँ। अतः आज हम तमाम बिन्दुओं को ध्यान में रख कर शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध रोशनी लोगों को कैसे मिले, संविधान के आर्टिकल 12 एवं 21 की अनुपालना हम सब मिल कर कैसे कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रख कर आज की इन जनसुनवाई को स्थगित करके इनका पूरा साहित्य तीनों ब्लॉकों का, दो हिन्दो में सहजवादी लोगों को उपलब्ध करावे, जन प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से कहे, सभी लोगों

१३४ अभिकारी
 १३४ अभिकारी
 १३४ अभिकारी

(समालोचन जी.नरसिंह)
 अतिरिक्त शिक्षा कलेक्टर
 १३४

को संतुष्ट करके यदि आप उद्योग लगाओ तथा लोगों को सम्पूर्ण जानकारी दें। बाद अगर हम जन सुनवाई करें, तो ही यह जन सुनवाई साकार होगी। अतः आज की तीनों जन सुनवाई 3सी1, 3सी2 एवं 3डी1 ब्लॉक को स्थगित करके नई तारीख मुकदर कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवैध करके पर्यावण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई करें।

श्री रामकुमार सोलंकी निवासी हरिमा ने कहा कि मैंने डेढ़ घण्टे पहले डिस्पले के दूसरों को दर्शाने के लिए कहा था, मैं मेरे प्रिंटिंग प्रेस से अभी बैनर तैयार करूंगा, जब ये डेढ़ घण्टे से डिस्पले पर नहीं दिखा सके तो ये क्या पेड़ लगा देंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि अगर कोई भी बात कहता है तो उसे सुनना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, एक-एक चीज इन लोग लिख रहे हैं तथा ये बैनर भी छप गये हैं, हमारी टीम काम कर रही है। तो अब कहीं सारे लोग उनको भी बोलने का मौका दो। बैनर अभी लगा देते हैं।

श्री मनीष मिर्धा, निवासी कुचेरा ने कहा कि पूर्व में जो अंबुजा में हुआ वहीं इतिहास यहां दोहराया गया, दो दिन पहले विज्ञप्ति छपती है, कौन देखता है, कहां छपती है, कितनी बड़ी छपती है, कोई अंदाजा नहीं। मैं इस आंदोलन से पहले नहीं सुझा हुआ था परन्तु जिस दिन इन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ उस दिन मुझे पता चला कि 34 दिन से हमारे घर बैठे हैं, जब ये हॉस्पिटल थे तो वहां पहुंचा एवं तब पता चला कि क्या हुआ है और यह सब इस आंदोलन पर क्यों बैठे हैं। उसके बाद से ही लगातार डेह, सरासनी, हरिमा आदि गांवों के सम्पर्क में हूं। जैसे-जैसे नये मुद्दे सामने आ रहे हैं, किसान महापंचायत भी की तथा पंजाब से भी किसान आगे उन्होंने भी सभी बातें कहीं। यहां की एक विशेष मांग थी, जो कलेक्टर सहित के नाम जापान दिया तथा आप लोगों को भी भेजी। विगत दो दिन से इन गांवों के वाट्सअप ग्रुप के माध्यम से मैं इनसे जे.एस.डब्ल्यू. द्वारा दी गई रिपोर्ट्स मांग रहा हूं, ताकि उस हिसाब से तैयारी करें, तो मेरे पास 3सी1, 3सी2, 3डी1 तीनों का सुनवाई हेतु पीडीएफ आये तथा तीनों पीडीएफ एक जैसे, 8 अथवा 9 पेज का एक पीडीएफ था, जिसमें केवल ऊपर हैडिंग में सी1, डी1 आदि अलग-अलग विषय हैं, इक्वेटेयर चीज दिया हुआ, बाकि सबकुछ लगभग एक जैसा। अब दो दिन से मैं उन्हें पढ़ रहा हूं, जिससे मुझे ये पता चला कि जे.एस.डब्ल्यू. ने इतनी मेहनत करके ये पता लगाया है कि इस विल में कितने सांप रहते हैं तथा इस विल में किसान नेवले रहते हैं। उस रिपोर्ट में बस इतना लिखा है कि इस गांव की जलवायु ये है, इस गांव में इतने नाड़े हैं, उसमें कोई डिटेल्स नहीं दी हुई। उसमें ऐसा कुछ बताया

श्री मनीष मिर्धा
मुख्यमन्त्री, अखिल भारतीय किसान सभा
नामूर (राजस्थान)

(अमरपाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नामूर

हुआ नहीं है कि हम इसें ठीक कैसे करेंगे जलवायु संरक्षण कैसे करेंगे, जल सार कैसे बढ़ायेंगे। केवल ये बताया है कि यहां इतना पानी है, यहां इतने वृक्ष लगे हैं। अब बताऊं ग्रीन कॉरिडोर की डिमांड अभी की नहीं, बहुत पहले की है। जब रोड कांस्ट्रक्शन यहां से चालू हुआ तो इन्होंने लिखित में दिया था कि हम यहां भी ग्रीन कॉरिडोर बनायेंगे। अभी वो ग्रीन कॉरिडोर छोड़ो, इन्होंने एक पेड़ तक नहीं लगाया। आप नपवा दो अथवा बता कि कौनसे ग्रीन कॉरिडोर बना है, कितने पेड़ लगे हैं। हम बात कर रहे हैं जे.एस.डब्ल्यू. की ये तो अभी चालू होगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही आप और हम अंबुजा सीमेंट में टकराव करके आपने उसका क्या नतीजा निकला, आपने जो बोर्ड लगाने का कहा था अभी तक बोर्ड नहीं लगा, वह जो अंबुजा सीमेंट वाले अपनी रिडिंग तक बता नहीं पाये और आज भी यहां पर जे.एस.डब्ल्यू. का एक और प्लांट यहां पर खड़ा कर रहे हैं, जिसमें कोई जानकारी नहीं है, दो दिन पहले छपता है, वो भी शायद डी1 का ही छपा था, बाकि छपा ही नहीं, जहां छपा उसकी अपने को जानकारी तक नहीं। आप डी1 का 4 वजे एक शुनवाई के लिए छाप देते हो और उसके बाद उसकी 8 पन्ने का एक पीडीएफ बन जाओ, जिसमें भी जलवायु जुड़ा कोई प्रावधान तथा एक्ज्यूआई कितना छोड़ेंगे, वहां पर तो हमने देख लिया, ब्रोंकाइटिस जैसी फेंफड़ों की बिमारियां हो रही हैं वहां के आसपास के एरियों की हालत खराब कर रही है। तो हम क्यों माने कि रोड जे.एस.डब्ल्यू. कुछ अलग करेगा। टेक्नोलॉजी तो जे.एस.डब्ल्यू. के पास भी अंबुजा के समान ही है। जब अंबुजा वाले एक्ज्यूआई, पीएम2.5, पीएल2.5 कास्ट्रोल नहीं कर रहे हैं तो यह कैसे करेंगे। मूण्डवा में हवा तो प्रदूषित है वो जलवायु को बर्बाद करेगा (डस्ट अथवा दूषित धूल) आती है, अगर कोई स्वरध कम्पाई वाला व्यापक वहां 10 मिनट रुक जाये तो वो भी खांसना शुरू कर देगा, उस खंख ही पीएम2.5 है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फैक्ट्री जब पांच गुणा बढ़ा देंगे तथा माईनिंग एरिया जब 15 गुणा बढ़ा कर देंगे, तब पीएम 2.5 को 60 रख लेंगे। हम पांच मीटिंग में ही पूछा था कि अभी का पीएम 2.5 कितना है, मैं भी कम्पनी रास्ते में बता पाये, जबकि आज के समय में गूगल पर 2 मिनट में सब आ जाता है। पर्यावरण दिवस के दिन भी आपस देखा तो पता चला एक्ज्यूआई 100 के पार है तथा पीएम 2.5 80 के पार है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम पांच गुणा बढ़ी फैक्ट्री बना कर भी 60 रख लेंगे। कोई भी फैक्ट्री किसी भी हालत में नहीं रख सकते। जे.एस.डब्ल्यू. वाले तो उससे भी ज्यादा एडवांस इन्होंने तो कहा था वो नहीं लिखेंगे कितना रखेंगे। ये तो लोगों को मारने में लगे हुए हैं। ना तो इनकी प्रति प्रति कॉस्ट है, ना ही ये माईनिंग प्लान से ये बता रहे हैं कि सीएसआर कितना छोड़ेंगे।

संजीव अग्रवाल
उपस्थित पत्र संयोजक
संजीव अग्रवाल

(उपस्थित पत्र संयोजक)
अश्विनी शर्मा
संयोजक

तथा उसकी क्या प्लानिंग है, लैण्डमार्क अचीवमेंट क्या होंगे। केवल 9 पेज का पीडीएफ बना कर दे दिया जिसमें केवल नाइलों के बारे में उनकी दूरियां, सांपों के, बंदलों के, मोरों के आदि के दिया दिया। जन सुनवाई से पूर्व अगर सभी फैक्ट्स सामने हो तो हम फैक्ट्स पर बात कर सके। अगर हम सभी को एक फाइलिंग दें तो हम भी रिफाईंड स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आप हमें पॉइन्टवाईज पूरी क्लियर देंगे तो हम पॉइन्टवाईज तैयारी करके आपको एक-एक चीज डिटेल में बता सकते हैं। हमारे पास केवल दो दिन पहले सूचना आई तथा उसमें भी केवल तीन पीडीएफ आये, उसमें में भी कोई डिटेल नहीं दी गई। जब आप माईनिंग करेंगे तो उसका प्रति यूनिट कॉस्ट तो होता है, प्रति यूनिट से माल निकालेंगे, उससे कितना फायदा होगा फिर इनकी मजबूरी भी तो है 2 प्रतिशत इस क्षेत्र में खर्च करने की, तो वो प्लान कहा है। पहले जब किसान महापंचायत की तथा कम्पनी वालों को भी बुलाया था तो अपने में केवल रेत और लू की थप्पड़ें ही खाई थी, कम्पनी से भी कोई आये ही नहीं अपने पास। तीनों जन सुनवाईयों को अलग-अलग करने का खर्च क्या है, जब वे पूरा जे.एस.डब्ल्यू का ही कर रहे हैं, सभी एक साथ ही क्या लेनी चाहिए। क्योंकि इन अलग-अलग ब्लॉक्स से केवल कन्फ्यूजिंग होता है। अपना पूरा माईनिंग प्लान एक साथ बता दो, जब ब्लॉक तो आपका पूरा ही पता है, ये सी1, सी2 आपके क्वार्टिजिफिकेशन है, हमें उससे क्या लेना। तो हमें तो पता साथ ही पूरा प्लान डिटेल में बता दो। पर्यावरण के प्रति आपको क्या इम्पैक्ट हुआ तो सब डिटेल में बता दो। जो पीडीएफ है उसमें सभी रिडिंग्स बनाई गई है यह करेंट रिडिंग्स हैं, कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि हम उस पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे, जब इम्पैक्ट का पता चले तो उसकी पर्यावरणीय सुनवाई करें, आप पता कर दे देंगे कि अभी टेम्परेचर 42 डिग्री है, परन्तु ये नहीं बताते कि हम कितना बढ़ायेंगे 42 का 45 करेंगे या ज्यादा। 42 डिग्री लिखने से क्या होना था तो हमें पहले से पता है, आप अपना प्रभाव बताये। एक्यूआई तथा पीएम 2.5 पर आप कितना प्रभाव डालेंगे। दूसरी बात अभी अंबुजा के आसपास के एरिया का पता, वहां माईनिंग ब्लॉस्ट के कारण उस क्षेत्र के स्कूल, विडिडिंग्स, घर आदि पर दरारें आ रही हैं। रुपाभर की स्कूल का आपका ध्यान ही है, मेरे पूरा विडिडिंग्स का कर सोशल मीडिया पर अपलोड है, जब 2 वजे साइरन बजने के बाद वहां फूट-फ्लास्टर गिरने लगता है, जिससे पट्टियां में कम्पन होने लगता है। वह माईनिंग क्षेत्र से महज 600-700 मीटर ही दूर है। यहां पर ब्लास्टिंग एरिया कितना लम्बा होगा, ब्लास्टिंग एरिया का प्रभाव कहां-कहां पहुंचेगा। आप ये मत सोचना कि ब्लास्टिंग केवल स्कूल में फ्लास्टर गिरना, ब्लास्टिंग कम्पन एडरस पूछ कर नहीं आता।

क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नवीन (गुजरात)

(धर्मालाल जीनार)
जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नवीन

घरों में भी आयेगा। कम्पन हर जगह पहुंचेगा, क्योंकि इनकी रिपोर्ट में मुझे कहीं नहीं मिला कि क्लारिस्टिंग एरिया कितना लम्बा है तथा कितनी दूरी तक प्रभावि करेगा। इन्होंने बस इतना ही दिया कि हम क्लारिस्टिंग को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, कम से कम क्या होता है, कोई ब्राइटरेरिया होना चाहिए। हम कोई छोटी-मोटी दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी कम्पनी की जिसका अरबों का बजट है एवं करोड़ों की रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो हम कम-से-कम ये तो उम्मीद करें कि हमें जो रिपोर्ट देंगे वो इंग की रिपोर्ट देंगे। हमें चाहिए डिटेल रिपोर्ट जिससे हम हमारी तैयारी कर सकें। मैंने अलग-अलग जगहों पर इसलिए कहा क्योंकि एक साथ में कन्फ्यूजन होता है। परसों शाम को सूचना मिली कि जन सुनवाई 1 बजे है, कल रात को सूचना मिली कि 10 बजे से शुरू हो जायेगी, तब उन्होंने बताया कि ये सी1, डी1 और सी2 सब अलग-अलग है। अब सभी का एक साथ ही छपवा देंगे, क्योंकि जन सुनवाई भी एक ही जगह है, तो मुझे भी एक साथ एक राष्ट्रीय न्यूजपेपर तथा एक ऐसा पेपर जो यहां के लोकल लोकल पड़ते हो, ये की ये समस्या अंबुजा में थी। उन्होंने छपवाई "द इंडियन एक्सप्रेस" यहां कई भाईयों ने तो "द इंडियन एक्सप्रेस" का नाम तक नहीं सुना, इंडियन नाम पर केवल इतना पता है कि हम इंडियन हैं। यहां के स्थानीय लोगों के पढ़ने वाले दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका अखबारों में छपवाये तथा एक प्रॉमिनेंट स्थान पर हिन्दी में छपवाये जिससे लोगों को देखने तथा समझने में आसानी हो। कल रात को मुझे सही से पता चला कि एक्जुअल टाईम क्या है इन जन सुनवाई को। आपको यहां पर घोटालेबाजी नहीं करके व्यापार करना है और व्यापार को बढ़ावा खिलाफ नहीं है परन्तु गुमराह मत कीजिए। लोगों को एडवांस में जानकारी दी, डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, जिससे ये पता चले कि ये करना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आगे अगर पर्यावरणीय स्वीकृति देनी है तो उस पर विस्तृत चर्चा हो जाये, कोई कहीं नहीं जा रहा है, रहना तो सबको यहीं है। अंबुजा के आसपास के काफी ऐसे एरिया है, जो रहने लाइक नहीं बचे, वो लोग जो डिस्ट्रेस हो गए, हमारा जन सुनवाई के लिए यह उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, अपनी बात कहें तथा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यहां खुली बेहस हो, यहां किसी को किसी से कोई पर्सनल बेर नहीं है, सबका एक ही है कि यहां के लोगों का जीवन खुशहाल हो तथा यहां की तो पहले से ही बहुत समस्याएँ हैं, प्रशासन ने तो बीच में ही डंडें मार कर उठा दिया यहां से, पहले तो समस्या तो सुलझी नहीं और आप इन्हें पर्यावरण एनजोरो और दे रहे हो। यहां पर एक समस्या तो निराली है कि इस कम्पनी कई-कई जगह तो एरासी-एसटी भी


 क्षेत्रीय अधिकारी
 पर्यावरण तथा पशुधन निर्वहण मण्डल
 जयपुर (राजस्थान)


 जयपुर
 22/11/2019

जमीनें बीच में छोड़ दी, इन्होंने खरीदी नहीं, क्योंकि फिर वो जमीन बीच में जो जायेगी तो उसके पास रास्ता ही नहीं रहेगा। जिनको भी 4 लाख, 8 लाख या 20 लाख जो भी अलग-अलग भाव मिले है, वहां पर ही वो 40 हजार में ही बेचना के लिए मान जायेगा, क्योंकि वो घिर चुका है, उसके पास कोई रास्ता है, ना कोई जगह तो वो क्या करें। इनकी जो पहले से जन समस्याएँ हैं वो तो हमने सुलझाई नहीं, और अब कह रहे हैं कि इनको पर्यावरणीय क्लियरेंस देना है या नहीं देना। अब भी उस क्लियरेंस का मतलब है जिसकी इन्होंने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। अब मेरा सुझाव है कि हम इस जन सुनवाई को आज कैंसल माने, इसका एक तरीका जो एड छपवाये, सभी आसपास के गांवों को फ्लायर भी बांटे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रभावित लोग आये, अपनी बात कहे। यहां पर सभी समस्याओं की जन सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर्यावरण का नाम दे देने से बाकि सभी समस्याएँ डकड़ में हैं। जब सलाहों में भीतरी प्रभावित हुई तब कलेक्टर साहब को समस्याओं को लेकर लिखित ज्ञान दिया गया, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ। जन सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को विस्तृत जानकारी हो, वो अपनी सभी प्रकार की समस्याएँ रख सके। भविष्य की बात करे तो बुजुर्ग लोग इस फैक्ट्री को इतना प्रदूषित नहीं पायेंगे पर उनके बच्चे जिन्दगी भर उस प्रदूषण को झेलेंगे। तो अपने बच्चे बच्चों का भविष्य भी सोचना है। जब बड़ी कंपनियां आती हैं तो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार रोजगार की होती है, लेकिन आप अंबुजा से देख लो कितने लोगों का रोजगार मिला है, सभी बाहर से लाते हैं। यहां जे.एस.डब्ल्यू में अभी तक किसी लोकल लोगों को रोजगार मिला गया। जब एक तरफ आप इन्हें कुछ दे भी नहीं रहे हो और ऊपर से इनका स्वास्थ्य भी खराब करेंगे तो यह क्या काम आयेगा। इनकी 5 पेज की पीडीएफ रिपोर्ट में मार्किंग प्लान, प्रति यूनिट कॉस्ट डिटेल्, सीएसआर खर्च, सीएसआर एम्प्लॉयमेंट आदि जैसी कोई डिटेल् नहीं हैं। कॉरपोरेट जगत में रिस्पोसिबिलिटी फण्ड, जिसमें अगर कंपनी यहां से 100 रुपये कमाती है तो कंपनी का फर्ज है कि वो 2 रुपये आपके यहां विकास कार्यों में खर्च करें। अंबुजा का आज 5-10 साल बाद यह तो माना कि हम एक स्कूल बना कर देंगे, हालांकि वो स्कूल नहीं बनी। कम-से-कम अपने कार्यों को एक टारगेट दे कि हम ये करके देंगे। फैक्ट्री दोस्ताने अपने मुनाफे के लिए बना रहे हो जनता के लिए क्या कर रहे हो, जनता का धन। एक बात और जब बात पेड़ की कटाई की आती है तो यह पेड़ काटते समय उसकी जो दूरी होती है, ये उसे नॉन डेंस फॉरेस्ट में मान कर काट लेते हैं फिर ये वादे करते हैं कि हम डेंस फॉरेस्टेशन करेंगे। डेंस फॉरेस्टेशन में वो जो डिस्टेंस लेते हैं, वो कटाई को डिस्टेंस से दो गुणा या तीन गुणा डिस्टेंस करेंगे

संस्थान राज्य प्रमुख निदेशक प्रमुख
भारत (राजस्थान)

राजस्थान (राजस्थान)
भारत (राजस्थान)

है, यागी ये कटाते तीन पेड़ है और लगाते केवल एक पेड़ ही। जो डि-फॉरेस्टेशन होता है, उसमें डेंस से डेंस करते है तथा वापस रि-फॉरेस्टेशन वो दूर डिस्टेंस करता है, जिससे वापस पानी भी नहीं पिलाया जाता, जब तीन पेड़ की जगह एक पेड़ लगाते है तो उनके बीच दूरी भी इतनी होती है कि इनके भाइय भी नहीं पहुंच पाएंगे जिससे वो पोधा वही जल कर मर जाता है। कम्पनी ने ग्राम वॉरिडोर में कहा कि हम रि-फॉरेस्टेशन करेंगे, तो आज तक कम्पनी ने इतना प्लांट खड़ा कर सिर्फ चिमनियों तक पहुंच गये है, कम्पनी ने एक प्लांटेशन नहीं किया। रि-फॉरेस्टेशन कम्पनी का क्या प्लान है, कुछ पता नहीं। बस इतना ही है कि इतनी खुदाई कर लेंगे, इतने बड़े-बड़े हेक्टेयर के ब्लॉक्स हो गये, हमें इन सब से क्या करना? कम्पनी तो हमें ये बताये कि इन ब्लॉक्स से ये जो निकालेंगे, उसका मुनाफा जमाना, तक कैसे पहुंचेगा? जन सुनवाई का मतलब तो यही होता है कि जनता की सुनवाई करनी, ना कि जन सुनवाई मतलब जे.एस.डब्ल्यू. की सुनवाई करनी। एडीएम से मेरी अभी तक आपसे यह शिकायत है कि मैं तीन दिन पहले ही अंधुजा के सामने रुक निकला हूँ, वहां ऑनलाईन मॉनिटरिंग बोर्ड अभी तक वाटर रीडर पर नहीं लगा है तथा मैंने उस फौवट्री के सामने रुक कर फौवट्री के अन्दर लगे बोर्ड जिसके बारे में कम्पनी वालों ने बोला था कि फौवट्री के अन्दर इसका बोर्ड लगा है, को देखने का कोशिश भी की थी, लेकिन वो बोर्ड भी कहीं नहीं दिखा। मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम पहले कम्पनी से माईनिंग प्लान तथा एन्वायरमेंटल प्लान लेवे, क्योंकि एन्वायरमेंटल प्लान के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं दिया। एन्वायरमेंटल प्लान डिटेल् में लेवे तथा हमें भी समय देकर हमें वाटरआप आदि शोशल भीडिया एन्वायरमेंटल प्लान दीजिए, ताकि वह प्लान हम सब के पास हो, हम उसको भी करके तैयारी करें। अब मैंने एक-दो दिन कोशिश कर ली, जिससे मुझे बस यह पता चला कि उस गांव के, उस अंगोर में तीन नेवले निकले, उस तात्वाच के पान को सांप निकले, मुझे बस यही समझ आया। कम्पनी ने केवल वर्तमान रिडिंग प्लान कंडी पर भी प्रोजेक्टिव रिपोर्ट नहीं दी, कम्पनी द्वारा पर्यावरण का कितना नुकसान पहुंचाया जायेगा, वो बतायें, जिससे डिटेल में डिस्कशन हो, करना बातें रिपिट हुआ जायेगी। अतः एडीएम महोदय आज की इन तीनों जन सुनवाईयों को निरस्त मान लें हुए, आगामी समय में स्थानीय अखबारों में छपवा कर, जनता को पूर्व में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवावे तथा उसके बाद जन सुनवाई करावे। फिर आप यहां जे.एस.डब्ल्यू. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के एक्सपर्ट को भी लाने की जरूरत ना दिखे दे इतने पॉइन्ट होंगे। आज की तारीख में मुझे बहुत ज्यादा है, इतने मुद्दे हैं कि अपन इस जन सुनवाई को आज की तारीख में कैंसल मान सकते है और उसकी

अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी

अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी
अधीनस्थ अधिकारी

आगे हम तैयारी करके आयेगे, आप इसकी जो पूरी डिटेल्स देंगे, उसको पॉइन्ट टू पॉइन्ट चर्चा कर लेंगे। एडीएम साहब आप हमें एक मौका तो दो डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। डीपीआर जब तक हमारे पास नहीं आयेगी तब तक इस जन सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, 8-9 पन्नों की पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। आम पर्यावरण को जो हानि होगी, इन्होंने केवल रिडिंग्स बताई है। हमें डीपीआर प्रोवाइड करवाये, जिससे यहां ज्यादा लोग आयेगे, ज्यादा मुद्दे आयेगे, आपके मुद्दे भी क्लियर हो जायेंगे, आपको भी बातें समझ आयेगी। अतः इस जन सुनवाई को कौंसल मानने और जन सुनवाई हो, इन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हो, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ।

श्री हनुमान भाकर, निवासी नागौर ने जन सुनवाई में अपने बिन्दु रखते हुए कहा कि इस लोक सुनवाई का प्रचार-प्रसार नहीं हुआ, किसी ऑफिस के माध्यम से अथवा आपके माध्यम से भी कोई सूचना नहीं है कि यह सुनवाई इतने बजे यहां है। जन सुनवाई से कम-से-कम 7 दिन पहले गाड़ी गांव-गांव, गली-गली गुमनाम से यह पता रहे लोगों को कि यह जन सुनवाई इस तारीख को है, ताकि जो इलाका प्रभावित है, वो कम-से-कम यहां आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सके। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, कम्पनी की जो मॉनोपोली है, ब्लॉक आवंटन दूसरे गांव हरिमा, सरासनी, भदानी और डेह में हो रखे है, जन सुनवाई हो रही है जिन्दास में उसके पीछे क्या कारण है, जन सुनवाई जहां ब्लॉक आवंटन हो रखे है, वहां लोग आये, लोग वहां प्रभावित है, जिन्दास तो पड़ोसी है, यह बात में प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित है जिनके खसरों ब्लॉकों में आये हैं। कम्पनी का इंटेंशन इन निवासीयों को लग रहा है, जन सुनवाई करनी कहा चाहिए और चुपके से वहां दूसरे गांव में लोक सुनवाई करके इतिथी कर ले तथा चुपके से रजिस्टर भेजकर लोगों से साइन करवा ले, इस प्रकार जन सुनवाई नहीं होगी। जन सुनवाई विधि के तहत से कम-से-कम 7 दिन का टाइम हो तथा बिन्दुवार बात हो। तहसील में आठव जय छोटी-छोटी बातों के लिए आप जब आमजन तथा गरीब लोगों को एडिटेड हो जाते हो, सभी कानून की किताबें बताते हो, लेकिन जब ये बड़ी कम्पनी खुले में सबके सामने रोड़ खोद कर काम चला रही है पूरे दिन, यहां कोई एक्सीडेंट हो गया अथवा रात को कोई गिर गया, इसका जिम्मेदार कौन है, इनके खिलाफ आप कार्यवाही करके अवगत करवाये या इन्होंने आपसे परमिशन ली है रोड़ खोदने की तो वो आप सार्वजनिक करें। ऐसा ना हो कि जे.एस.डब्ल्यू आपका आयोजन करे कोई कागज भेजे, जो आपके मुकदमे बंद जाये, परन्तु आम आदमी जब अपनी आपत्ति बोझ लेकर आपके पास दर्ज करवाने आवे, तो वो कागज तीन-तीन महीने आकरी

शेखी अफिया

जन सुनवाई प्रमुख निर्वाचन अधिकारी
नागौर (जिलाधिकारी)

(सम्पादक जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर

टेबल के नीचे पड़ा रहे। अतः आपसे ये निवेदन है कि आज की इस जन सुनवाई को, जो कम्पनी की मोनोपोली से मनमर्जी की जन सुनवाई है, जनता को सुनने के लिए सही वक्त निर्धारित करें तथा उसके अनुसार ये जो 9 पेज की पीडीएफ बता रहे हैं, इस प्रकार की पीडीएफ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें स्थानीय भाषा में बड़े अक्षरों में कम्पनी की सारी डिटेल् लिखी हुई रिपोर्ट कम्पनी द्वारा बनाने वाली है और क्या किया है। 8 साल से तीन कॉरिडोर को बंद कर रहे हैं, 8 साल में पौधे पौधे बढ़े कर दिया कम्पनी ने, पौधे लगे हुए कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, गमले पंजर इधर-उधर रखे नजर आते हैं, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हर आदमी दो-दो पेड़ लगाये, वन्दे गंगा, पानी को लेकर सरकार किस प्रकार के काम कर रहे है और कम्पनी का कोई सिस्टम ही नहीं है, ना पानी है ना ही पुनर्वास का व्यवस्था की व्यवस्था की आप लोगों ने, जिनके खसरे कम्पनी की जमीनों में आये उन लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था इस 9 पेज के पीडीएफ में जिक्र तक नहीं है। इसमें जिक्र केवल प्रोडेशन आदि का है, उससे आम आदमी को क्या लेना देना। आम आदमी यहां रहेगा उसको सुविधाएं क्या दोगे आप, उनका भला कैसे करेंगे, ये सारी चीजें डिटेल् में हो, तब आपकी लोक सुनवाई का मतलब पूरा होगा वरना ऐसी लोक सुनवाई से कोई फायदा नहीं है। मेरी प्रार्थना ये होगी कि आज की जन सुनवाई रद्द हो तथा नये सिरे से आगामी दिनांक में सादेख तब ही उसका पूरा बायोडाटा स्थानीय भाषा में, बड़े-बड़े अक्षरों में बुकलेट सभी को उपलब्ध कराये।

श्री अनिल बारूपाल निवासी डेह ने कहा कि उपस्थित मौजिद ग्रामीणों को धन्यवाद देता हूं, कि आपने इस लोक जन सुनवाई की सूचना को गंभीर लेकर आपने हम एवं अधिकारों के लिए जागरूकता दिखाई तथा यहां संकण्डों की सख्या में कमी मौजूद हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार! मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनको जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी से नाश्ते एवं खाने का लालच देकर बुलाया और उन्होंने भी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहां आने से तथा लोगों की बातें सुनने से उनका भी जमीर जागेगा और निश्चित रूप से वो इस जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी के खिलाफ आन्दोलित होंगे। कम्पनी ने जो लोक सुनवाई रखी है, वो 3सी1, 3सी2 एवं 3डी1, इनमें सरासनी, हरिमा, भदाना तथा डेह का काफी लम्बा बाड़ा क्षेत्र आता है और सबसे कम क्षेत्र जिन्दास गांव का आ रहा है, फिर भी इन्होंने जन सुनवाई के लिए जिन्दास को चुना इसके पीछे मुझे इनकी मंशा खुल गइवड़ नजर आ रही है, क्योंकि जिस गांव का एरिया ब्लॉक में ज्यादा आ रहा है उस गांव को चुनते। अभी जो जगह चुनी है यहां ना तो साखन की व्यवस्था है,

लेनीय अधिकारी
नगरपाल राज्य प्रबुधन निर्वहण मण्डल
नागा (राजस्थान)

(अ.च.रा.स.जी.न.म.)
अतिरिक्त सहायक
नागा

भी लोग आसानी से पहुंच सकते हैं, मैं मंच के माध्यम से ये जानना भी चाहूंगा कि लोक सुनवाई की परिभाषा क्या है, ज्यादा लोगों को बुलाना अथवा ऐसी जगह चुनना, जहां कम लोग आ पायें? मेरे विचार से तो कोई बड़ा गांव चुनते, जिसमें ज्यादा लोग उपस्थित होते, लेकिन उसमें इनको डर था कि वहां लोगों का आक्रोश भेलना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इस लोकेशन को चुना। अतः भवनीय एडीएम साहब तथा आरओ साहब से निवेदन है कि इस लोक सुनवाई को स्थगित करके नई तारीख देकर दुबारा से लोक सुनवाई की जाय, उसकी प्रोपर सूचना भी दी जाये। यहां हम लोगों तक को पता नहीं था कि आज तीन ब्लॉकों की सुनवाई है, कभी कोई कह रहा है कि 1 बजे से, कोई 10 बजे से, कोई 4 बजे से। कभी एक ब्लॉक की बताते हैं कभी तीन ब्लॉक की, तो प्रोपर जन सुनवाई नहीं हो पाई। प्रोपर इसका प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया। जो जन प्रतिनिधि हैं, जागरूक लोग हैं उन तक सूचना नहीं पहुंच सकी। प्रोपर सूचना के अभाव में षडयंत्र पूर्वक लोक सुनवाई की जा रही है, अतः इसको रद्द किया जाना चाहिए। जिन कास्तकारों की जमीन इन ब्लॉकों में आ रही है, उन कास्तकारों से जमीन लेने के बाद उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था होगी। स्थानीय लोगों को किस आधार पर रोजगार दिया जायेगा। तीज एरिया में हजारों की संख्या में राजकीय वृक्ष खेजड़ी मौजूद है, खेजड़ी को बचाने के लिए राजस्थान सरकार तथा केन्द्र सरकार कह रही है, यहां का खेजड़ी वृक्ष किसानों के लिए वरदान है, इसकी सांगरी जो सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती है तथा बहुत मछम दामों में बिकती है, खेजड़ी के पते जो लूंग, वां पशुपालन के चारे के काम आते हैं, तो जब हजारों की संख्या में यह पेड़ कटेंगे, ये कह रहे हैं कि पेड़ लगा भी वे नहीं परन्तु एक वयस्क पेड़ के बदले 50 पेड़ भी लगाये तो वो भी कम है, तो इससे भी किसानों को भारी नुकसान होगा। इस एरिया में केर के पौधे भी बहुत हैं, केर वाकम राजस्थान में ही होता है और केर से भी किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, वो भी खत्म हो जायेंगे, उससे भी किसानों को भारी नुकसान होगा। खनन से पर्यावरण प्रदूषित होगा, उससे आसपास का जन जीवन तथा आसपास के जल क्षेत्र प्रभावित होंगे, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, इन सब बातों के सम्बन्ध में भी कम्पनी ने कोई स्पष्ट विवरण अपनी बुकलेट में नहीं दिया। खनन क्लारिफिकेशन से उस क्षेत्र की रहवासी द्वाणियों में नुकसान तथा भविष्य में जन हानि हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। खनन क्षेत्र में जब युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा, तो यहां का आमजन, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु सभी प्रभावित होंगे तथा प्रदूषण से उन पर जो दूष्प्रभाव पड़ेगा, उसका आंकलन कम्पनी द्वारा किस प्रकार किया जायेगा, चाहे तब तक

शेरीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रमुख निर्देशन मण्डल
जयपुर (राजस्थान)

(जयपाल जीनर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जयपुर

के स्वास्थ्य के प्रति हो, उससे सुरक्षा कैसे करेंगे? उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया। बहुत से तथ्य कम्पनी ने छुपाये हैं, जैसे खनन क्षेत्र में 10 किलोमीटर रेडियस में 19 बड़े तालाब हैं, जिनकी नारायण जी ने खसरा सहित जानकारी दी, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो दर्ज नहीं है छोटे नाड़े-नाड़ियां वो भी कम-से-कम 40 से अधिक हैं। जिन सब को कम्पनी ने छुपा कर क्या संदेश देना चाहती है। यह जनता के विकास की बात करते हैं, सरासरी एवं हरिमा के किसान जो इस कम्पनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे 127 दिन से लोग बैठे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, वो विकास सबने देखा होगा। उसी ब्लॉक में बहुत खसरे आ रहे हैं, सैंकड़ों परिवार बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन कम्पनी ने अपनी फाईल में श्रमशक्ति दिखाई केवल 91 लोगों की। अतः आपरो यही निवेदन रहेगा कि ना तो इसकी प्रोपर सूचना हुई, ना ही यहां लोग पहुंच सकें। अतः इस लोक सुनवाई को स्थगित करके इससे सम्बन्धित जो भी रिकॉर्ड पहले पब्लिक के सामने लाये जाये, उनका हिन्दी में अनुवाद करके लोगों तक उपलब्ध करवाया जाये, ताकि वह समझ सके कि जे.एस.डब्ल्यू. कम्पनी हमारे लिए क्या-क्या योजना तथा क्या-क्या प्लान कर रही है। कम्पनी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि प्रतिदिन 2 शिफ्ट में काम चलेगा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने घण्टे काम चलेगा, अगर 24 घण्टे काम चलता है तो 2 शिफ्ट का मतलब हो गया कि एक श्रमिक 12 घण्टे काम करेगा, जो कि उसके अधिकारों का हनन है। एक बात और कम्पनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खनन के बाद जमीन में गड्ढे हो जाएंगे, उसमें 95 हेक्टेयर जमीन को पूनर्भरण कर दिया जायेगा तथा 176 हेक्टेयर को कम्पनी जलाशय के रूप में परिवर्तित करेगी, लेकिन अगर ये जलाशय के रूप में परिवर्तित करेंगे तो इतना जल कहां से लायेंगे। जब 18 मीटर से लेकर 40 मीटर तक इसकी खुदाई की जायेगी, अर्थात् 120 फीट से तो अधिक ही, उसको भरने के लिए पानी कहां से उपलब्ध होगा, 200 किलोलीटर पानी तो कम्पनी खुद को चाहिए, इतने पानी की व्यवस्था कहां से करेंगे और अगर उनके अन्दर गंदा पानी छोड़ेंगे तो वो जलाशय क्या काम आयेंगे। अपना हक गिड़गिड़ाने तथा मांगने में नहीं मिलेगा, हक के लिए लड़ना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आज की जन सुनवाई का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। इसको स्थगित करो।

श्री नारायण बेनिवाल, पूर्व विधायक खींवर ने कहा कि सभी बातें पूर्व वक्तों में बता दी हैं। हमारी मुख्य मांगें हैं कि एक तो भारती निषिधा 2006 के न्याय संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत माननीय कलेक्टर ने पूरे जिले में लागू है, ज्यादातर लोगों को ये पता था कि 5 से अधिक इकट्ठे हो नहीं सकते, इसलिए ज्यादा लोग आ नहीं


श्री नारायण बेनिवाल
 (अध्यक्ष) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
 नागौर (राजस्थान)


(श्री लालजी सिंह)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 नागौर

पाये। दूसरी बात कम्पनी ने लिटरेचर को छिपाने का प्रयास किया। तीसरी बात जब तीनों ब्लॉक्स की जमीनें सरासनी, हरिमा, डेह तथा भदाना में हैं, तो जन सुनवाई 8 किलोमीटर दूर जिन्दास में करना भी उचित नहीं है, जिससे कम्पनी का मेलाफाईड इंटेंशन जाहिर होता है। इसके अलावा जन सुनवाई का जो साहित्य लिखा है, इंग्लिश में इतना बड़ पुलिन्दा यह कह रहे हैं कि हमने कई जगह रखा, लेकिन यहां जितने भी वक्ता थे सबने यहीं बात कही कि इसके बारे में हमें कोई अता-पता नहीं है। इन तमाम बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि हो, हम उद्योग के खिलाफ नहीं, परन्तु जन हित सबके लिए सर्वोपरि है, हम तमाम लोग यह मांग करते हैं कि आज की जन सुनवाई को स्थगित की जाये तथा यह सी1, सी2 और डी1 तीनों की जो जन सुनवाई है, हम सब लोग तीनों जन सुनवाईयों का बहिष्कार करते हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि इस जन सुनवाई के सम्बन्ध में कोई और अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन-मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन सुनवाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में प्राप्त आक्षेप/सुझाव/आपत्ति "परिशिष्ट स" संलग्न है।

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री चम्पालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर (राजस्थान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता— 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट— 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा— 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉलर के साथ स्थापना, निकट गांव— हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील— नागौर एवं डेह, जिला— नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

①	—जिन्दास जीन्दा	ADN जिन्दा	
2	Raj Kumar Wera	R.O., RSPCB, Nagaur	
3	Hemant Kumar	JEE, RD RSPCB Nagaur	
4	SARTHAK TIWARI	JSO., RD, NAGOUR	
5	Raiveer Bhakar	S.A. collected	
6	Vaunode Jaini	JSW Nagaur	
7	Rajan K. K. K. K.	JSW Nagaur	
8	Arun Sharma	JSW Nagaur	
9	Madhu Kanakamedda	JSW Nagaur	
10	Arvind Sharma	JSW, Nagaur	
11	Ram Yadav	JSW, Nagaur	
12	Siddhanta Bhagwat	JSW Nagaur	
13	Amit Kumar	JSW Nagaur	
14	Shresh Karan	SHO तहसील नागौर	
15	Narsingh	TDR Ngs	
16	Radha Kishan	SHO Rall	
17	Schiram	Patwari	
18	HARIRAM SARAN	INSPECTOR (LR) BHADANA	
19	Ravindra	Patwari Harima	
20	Songeev Kr. Chandaliya	JSW Nagaur	
21	Bajranglal Pareek	H.M. GUPS JINDAS	

उपस्थिति पंजिका

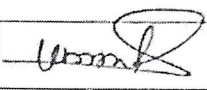
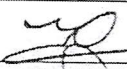
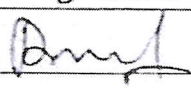
चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट- 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा- 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉल्वर के साथ स्थापना, निकट गांव- हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला- नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दारा संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

22	उम्मेदासीह	भदवा (बानाक)	
23	भदनी लाल	भदनी लाल	भदनी लाल
24	कल्याणसिंह	जिन्दारा	कल्याणसिंह
25	अशोक	हरिमा	अशोक
26	ज.श्री.रा.	हरिमा	
27	पू.रा.	जि.रा.	पू.रा.
28	हरिहरसाराह	भदवा	हरिहरसाराह
29	सोमेश्वर भाय	हरिमा	
30	मंगीलाल बाना	भदवा	Mangilal
31	पू.रा.	लालसारा	
32	रविन्द्र भाबू	सरसनी	रविन्द्र
33	Janki Chaur	Sarvasani	Janki
34	श.मेश्वर	डेह	
35	सनेलालदास	डेह	

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3री1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट- 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा- 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की बॉलर के साथ स्थापना, निकट गांव- हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला- नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दारा संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025

समय: प्रातः 10:00 बजे

36	मोनिका शर्मा	सरासूनी	
37	प्रकाश केजर	सरासूनी	
38	श्रीधर केजर	सरासूनी	प्रकाश केजर
39	कान्हा	जिंदारा	साधर केजर
40	शोभा	जिंदारा	कान्हा
41	समु	जिंदारा	
42	समु	जिंदारा	
43	नेहा	सरासूनी	नेहा
44	रोशन	सरासूनी	
45	रोशन	जिंदारा	
46	मोकाश	भड़ाना	
47	नितेश	सरासूनी	
48	प्रकाश	भड़ाना	
49	Neelam	जिंदारा	SS
50	मैजू केजर	हरिमा	मैजू केजर
51	कुल केजर	हरिमा	मैजू केजर
52	राज केजर	सरासूनी	मैजू केजर
53	साधु केजर	हरिमा	हरिमा
54	कुलडी	हरिमा	
55	श्रीधर केजर	हरिमा	
56	श्रीधर केजर	हरिमा	

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट- 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा- 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉल्वर के साथ स्थापना, निकट गांव- हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला- नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
57	पुशोला	भड़ाना	पुशोला
58	हरसुखराम	भड़ाना	हरसुखराम
59	हेमन्त	भड़ाना	हेमन्त
60	ताराम	भड़ाना	ताराम
61	गोपाल साहू	भड़ाना	गोपाल
62	हरविष्णु	डेह	हरविष्णु
63	लुबीला	भड़ाना	लुबीला
64	कोशल्या	॥	कोशल्या
65	आवना	॥	आवना
66	गोरी	॥	गोरी
67	रेजना	॥	रेजना
68	सैजना	॥	सैजना
69	आविष्का	॥	आविष्का
70	रेजना	॥	रेजना
71	शरणी	॥	शरणी
72	चिंका	॥	चिंका
73	जिंका	॥	जिंका
74	जिंका	जिंका	जिंका
75	प्रवीण	जिंका	प्रवीण
76	सलीश	सलीश	सलीश

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता— 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट— 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा— 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉलर के साथ स्थापना, निकट गांव— हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील— नागौर एवं डेह, जिला— नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दारस संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

77	उर्मिला साह	भदानी	उर्मिला साह
78	ओम प्रकाश	भदानी	Om Prakash
79	समुन्दर	भदानी	समुन्दर
80	मनोहर लाल	हरीमा	Manohar
81	नलथु नाथ	भदानी	
82	विष्णु	भदानी	Vishnu
83	विनायक	भदानी	विनायक
84	शमनिलाल	जिंदारस	
85	शमनिलाल	भदानी	शमनिलाल
86	शमनिलाल	भदानी	Sham Lal
87	विष्णु	भदानी	Vishnu
88	धर्मराम	भदानी	Dharmaram
89	जगदीश	भदानी	
90	हनुमान	भदानी	
91	गुरुलाल	भदानी	Gurulal
92	शमनिलाल	भदानी	Sham Lal
93	प्रियेश	भदानी	Prakash
94	अमर	भदानी	Amr
95	शिवराज	भदानी	Shivraj
96	जयपाल	भदानी	Jaypal
97	मनीष	भदानी	Manish

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट- 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा- 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की बॉक्लर के साथ स्थापना, निकट गांव- हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला- नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान- राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्ददास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

क्र	नाम	जिला	हस्ताक्षर
98			
99	शहीराम	जिंददास	गोविंदराज
100			
101	शहीराम	जिंददास	
102	गुलाम	जिंददास	
103	नवनाथ	डेह	
104	पिछू खाणा	डेह	
105	Mahipal	डेह	
106	Rajpooja	डेह	
107	सुहास	जिन्ददास	
108	तुलदास	जिंददास	
109	उमेश प्रकाश	सरासनी	तुलदास
110	कान्दाराभ	जिंददास	
111	महावीर शर्मा	डेह	कान्दाराभ
112	विजयराज भोंडा	डेह	मो
113	रेणुका केवर	सरासनी	रेणुका केवर
114	राधिका राठौड़	सरासनी	राधिका राठौड़
115	प्रकाश केवर	सरासनी	प्रकाश केवर
116	मधुकुंवर	सरासनी	मधुकुंवर
117	उन्मय केवर	सरासनी	
118	सुभन केवर	सरासनी	

सुभाष

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3री1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट- 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा- 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की बॉलर के साथ स्थापना, निकट गांव- हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला- नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दारा संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

129	लक्ष्मी	नागौर	
130	शरीफ	भड़ाना	शरीफ
131	रजनी	॥	
132	केलाश	भड़ाना	
133	निबिडी	जिंदारा	
134	रजनी	हरिमा	
135	संजुडा	भड़ाना	
136	अच्यु	भड़ाना	अच्यु
137	पपुडी	भड़ाना	
138	मरणा	जिंदारा	
139	मोहिलाल	मरणा	
140	पुन्याराम	मोहनवास	मोहनवास
141	केलाश	मोहनवास	मोहनवास
142	अखाराम	जिंदारा	अखाराम
143	हरिराम	मोहनवास	
144	हरिन	जिंदारा	
145	सुरेश	जिंदारा	
146	मोहनलाल	हरिमा	
147	राधिका	॥	
148	मनिषा	भड़ाना	भड़ाना
149	जीवनाराम	भड़ाना	राधिका
150	रवीप्रसाद	मोहनवास	मोहनवास
151	अजय		
152	शोभा		अजय

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय रवीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता— 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट— 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा— 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉल्वर के साथ स्थापना, निकट गांव— हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील— नागौर एवं डेह, जिला— नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

190	खेरा राजी जी	जिन्दास	
191	मंगलराज	जिन्दास	
192	सुखारजी	भड़ाना	सुखारजी
193	खेरा राजी	जिन्दास	खेरा राम
194	सुखारजी	जिन्दास	सुखारज
195	शिशुपाल	भड़ाना	शिशुपाल
196	राजराज	भड़ाना	राज
197	सुखारजी	भड़ाना	सुखारजी
198	सुखारजी	भड़ाना	सुखारजी
199	सुखारजी	भड़ाना	सुखारजी
200	साखा	जिन्दास	
201	प-नाराज	भड़ाना	प-नाराज
202	हरिराज	भड़ाना	हरिराज
203	हरिराज	भड़ाना	हरिराज
204	सुखारजी	जिन्दास	
205	विनोद जी	जिन्दास	
206	विनोद जी	जिन्दास	
207	सुखारजी	जिन्दास	
208	सुखारजी	जिन्दास	
209	सुखारजी	जिन्दास	

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट- 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा- 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉल्वर के साथ स्थापना, निकट गांव- हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला- नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दारा संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
210	हनुमानराम	भडाठा	हनुमान
211	देवानाम	भडाठा	देवानाम
212	बादर	जिन्दारा	बादर
213	श्रीराम	जिन्दारा	श्रीराम
214	सुरेश	जिन्दारा	सुरेश
215	जीवराज	मोड़वास	जीवराज
216	मनोज	कवलीर	मनोज
217	पप्पूराज	जिन्दारा	पप्पूराज
218	सुरेश	जिन्दारा	सुरेश
219	कपाराम	जिन्दारा	कपाराम
220	सुकेश	डेह	सुकेश
221	गोपालराम	जिन्दारा	गोपालराम
222	बादर	जिन्दारा	बादर
223	दीनलाल	भडाठा	दीनलाल
224	शिवराज	भडाठा	शिवराज
225	वैष्णवराज	प्र. अ. 213 जिला जिन्दारा	वैष्णवराज
226	सीताराम काना	भडाठा	सीताराम काना
227	चन्नाराम	हरिमा	चन्नाराम
228	गुनार	हरिमा	गुनार
229	पुनीत लाल	हरिमा	पुनीत लाल

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.उब्ब्यू सीमेंट लिमिटेड, 3सी। चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट- 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा- 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की बॉक्लर के साथ स्थापना, निकट गांव- हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला- नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान:-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
2301	श्री राधेश्याम शर्मा	पूर्व सरपंच अदाणा	
231	श्री कालूजी	जिन्दास	कालूजी
232	॥ चन्दीरामजी	जिन्दास	चन्दीरामजी
233	॥ चन्दीरामजी	अदाणा (समिन्दाजी)	चन्दीरामजी
234	॥ शुभनारायण	मोडवाला	शुभनारायण
235	॥ दिलीप	जिन्दास	दिलीप कुमार
236	॥ सुधराम	जिन्दास	सुधराम
237	॥ प्रेमलाल	अदाणा	प्रेमलाल
238	॥ मानवे-सीसिंहजी	हरिमा	मानवे-सीसिंहजी
239	॥ मनोहर	अदाणा	मनोहर
240	11. Harendran Singh	JM Environment Pvt. Ltd.	Harendran Singh
241	12. Pamesh Nelen	JM Environment Pvt. Ltd.	Pamesh Nelen
242	13. Prachi Saxena	J.M. Environment (P) Ltd	Prachi Saxena
243	14. Shankar Lal	Bhadana	शंकरलाल
244	15. Aduranyi	Bhadana	आदुराणी
245	16. Jagdish Rang	Bhadana	जगदीश
246	17. Chhagan Lal	देह	छगनलाल
247	18. कुलराज जी	अदाणा	कुलराज
248	19. केनाशजी	जिन्दास	केनाशजी
20.			

उपस्थिति पंजिका

चूना पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय रवीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना पत्थर खनन परियोजना, आवेदक मैसर्स जे.एस.डब्ल्यू. सीमेंट लिमिटेड, 3सी1 चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता— 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट— 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा— 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रेशर क्षमता 1600 टीपीएच की वॉलर के साथ स्थापना, निकट गांव— हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील— नागौर एवं डेह, जिला— नागौर (राजस्थान) में स्थित है।

स्थान—राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिन्दास संख्या 2, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर

दिनांक: 12.06.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

249	अजयपालजी	जिन्दास	अजयपाल
250	हितेश	Bhadrachand	हितेश
251	मंगला लक्ष्मी प्रजापत	भदवा	मंगला/शर्मा
252	मनिष	भदवा	मनिष
253	हरानन्द ईनाडिया	भदवा	तारानन्द
254	दामोदर	जिन्दास	दामोदर
255	सवाई सिंह	जिन्दास	सवाई सिंह
256	इजाराशम		इजाराशम
257	विक्रम		विक्रम
258	नथुराम	जिन्दास	नथुराम
259	रविन्द्र	जिन्दास	रविन्द्र
260	ओमाराशम	जिन्दास	ओमाराशम
261	उमेश सिंह	जिन्दास	उमेश सिंह
262	रामेशम गौरा	जिन्दास	रामेशम गौरा
263	शैलानराम प्रजापत	भदवा	शैलानराम
264	पूनाराम बैलदार	जिन्दास	



वरिष्ठ उपाध्यक्ष बोटु राम गोदारा, सभा अध्यक्ष अयाज खान, अध्यक्ष रामदेव गुलेरिया, महिला उपाध्यक्ष सुनीता चौधरी, मंत्री राजेश खिलेरी पुनः मंत्री पद सौंपा गया। इस अवसर पर

गई तथा सभी भागीदारों के द्वारा व्यवसाय जारी रखने का निर्णय लिया गया। हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के बाबत में किसी को कोई अपील हो तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, नागौर कार्यालय को 7 दिवस के भीतर सूचित कराए।

वार्ड मेसर्स श्री गणपति माई
भागीदारी
DNA3525

कैम्प जारी, बच्चों में उत्साह

कई बौद्धिक, शारीरिक व रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन



समस्या-समाधान, संचार, अस्तित्व, रचनात्मकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे कौशल सिखाना बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य निलेश शर्मा ने बताया कि समर कैम्प दिनचर्या की एकरसता को तोड़ने और बच्चों को रोमांचक गतिविधियों में डुबोने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उन्हें

समर कैम्प का मुख्य उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास करना है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। समर कैम्प प्रभारी अर्जुन आचार्य, वसीम अहमद व नेहा परिहार ने बताया कि समर कैम्प में रंजन कंवर और मनोज तिवारी ने योगासन, मेडिटेशन और ध्यान का अभ्यास करवाया। नेहा परिहार और प्रियंका काबरा ने बच्चों को जुम्बा नृत्य का प्रशिक्षण दिया। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में सुनील जूनी ने बच्चों को केनवास पेंटिंग का अभ्यास करवाया। बच्चों को प्रोजेक्टर की सहायता से प्रेरणादायक मूवी दिखाई गई।

गच्छता की शपथ दिलाई छात्रियों को किया जागरूक



गरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर तय और सीवरज योजना के प्रति शहरवासियों को जागरूक करने के लिए नाटक का सन्देश के अपना थियेटर के कलाकारों द्वारा शहर में 5 क्षेत्र में हास्य प्रधान नुक्कड़ नाटक का मंचन पब्लिक स्कूल, इलाइलों का मोहल्ला, भाटों में हास्य प्रधान नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाने, हास्य डायलॉग व नृत्य कर नागरिकों को घरेलू सीवर कनेक्शन के फायदे बताए। साथ जल संरक्षण के उपाय बताए और साफ सफाई रीके के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में के वे वैध पेयजल कनेक्शन और घरेलू सीवर बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि है। कार्यक्रम में कैप आरयूआईडीपी के देवेन्द्र की शपथ दिलाई।

छापला के सुधीर बने लेफ्टिनेट

गोटन। निकवर्ती छापला गांव निवासी सुधीरप्रताप सिंह जोधा का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होने पर गांव में खुशी की लहर छाई हुई है। मारवाड़ राजपूत सभा के केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवलसिंह जोधा छापला व मोहनसिंह जोधा ने बताया कि सुधीर प्रतापसिंह के लेफ्टिनेंट बनने पर परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कुलदेवी नागणेची माता, सिद्ध बाबा शिवनाथजी महाराज व अपने दादा सोनसिंह जोधा को दिया है। गौरतलब है कि सुधीर के दादा सोनसिंह जोधा स्वयं एक सामान्य किसान हैं परन्तु उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार उनके परिवार वाले शिक्षा व नौकरी के क्षेत्र में अक्सर हैं तथा जोधा परिवार को भारतीय सेना से गहरा लगाव है। सुधीर प्रताप सिंह जोधा के पिता महेन्द्रसिंह जोधा भारतीय सेना की 25 वीं राजपूत रेजीमेंट से सेवानिवृत्त हैं व वर्तमान में आबकारी विभाग में कार्यरत हैं तथा माता मंजूकंवर गृहिणी हैं। उनके बड़े पिता भवरसिंह जोधा भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं व चाचा नवलसिंह जोधा छापला भारतीय सेना की 16 वीं राजपूत रेजीमेंट से सेवानिवृत्त हैं।



गेम में निर्णायक नियुक्त

ओर से 15 मई तक पटना में आयोजित डिया गेम में निकटवर्ती ग्राम बंवरला के री को भारतीय एथलेटिक संघ ने एथलेटिक निर्णायक नियुक्त किया। राजस्थान से बनाए गए, जिसमें नागौर से अकेले हरिराम धरि तीसरी बार खेले इंडिया प्रतियोगिता है। चौधरी को नेशनल स्तर पर निर्णायक राजस्थान एथलेटिक संघ, नागौर जिला संघ, जिला तीरंदाजी संघ एवं खेल प्रेमियों पटना के लिए रवाना होंगे।

प्रधानाचार्य सैनी ने संभाला कार्यभार

संखवास। कस्बे के पीएमश्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहली बार प्रधानाचार्य की स्थाई नियुक्ति हुई है। भामाशाह प्रेक ओमप्रकाश गोड ने बताया कि प्रधानाचार्य के रूप में मंगलवार को ही धर्मवीर सैनी ने विद्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विद्यालय प्रशासन ग्रामीण एवं भामाशाह द्वारा प्रधानाचार्य का स्वागत किया गया। साथ ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य आदम अली, राधेश्याम रामकिशोर, विनोद बाकल, प्रहलाद राम, ज्योति, कल्पना, हरसुख देवासी आदि मौजूद रहे।



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District-Nagaur 341001, email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "मैसर्स जे एस डब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, 3 सी। चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट @ 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा @ 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रशर क्षमता 1600 टीपीए की वांछित के साथ स्थापना, निकट गांव हरिमा, भड़ना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला-नागौर (राजस्थान) की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
- और चूंकि मैसर्स जे एस डब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
- और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
- और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नलिखित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - संस्थानिक क्षेत्र, झालाना झूंगरी, जयपुर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जयपुर। 4. जिला कलेक्टर, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर। 6. CEO जिला परिषद नागौर। 7. उपखण्ड अधिकारी, नागौर। 8. तहसीलदार नागौर। 9. तहसीलदार डेह। 10. क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर। 11. जिला उद्योग केन्द्र नागौर। 12. विकास अधिकारी पंचायत समिति, नागौर। 13 ग्राम पंचायत, हरिमा 114. ग्राम पंचायत, भड़ना। 15 ग्राम पंचायत डेह। 16. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिंदास सं. 02. पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर।
- उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 12/06/2025 को प्रातः 10:00 बजे स्थान-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिंदास सं. 02, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला- नागौर में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी
DNA 3525

कार्यालय नगर परिषद, नागौर आम सूचना						दि. 07.05.2025
क्रमांक : नपना/क.सू./2025-26/603						
इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा अपनी खरीद शुदा भूमि का आवसीय/व्यावसायिक/मिश्रित प्रयोजनार्थ रुपान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात् -						
क्र.सं.	नाम व पता	प्रयोजनार्थ	मौजा, खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	आस-पड़ोस	
1.	प.सं. LSGCU90A/2025-26/104624 श्रीमती सिद्धि कुमारी पत्नी श्री नरेश, जाति जाट, निवासी बुडी, तहसील व जिला नागौर	90-ए आवासीय	अमरपुरा 344	क्षेत्रफल 1347.08 वर्गमीटर	उत्तर में नागौर डेह रोड दक्षिण में इसी खसरे की शेष जमीन पूर्व में खसरा नं. 345 की जमीन पश्चिम में ख.नं. 1108/344 की जमीन	
2.	प.सं. LSGCU90A/2025-26/104487 श्री मोहम्मद जावेद गौरी पुत्र श्री हाजी अनवर जाति मुसलमान गौरी, निवासी नागौर, तहसील व जिला नागौर	90-ए आवासीय	वेनार साणवास की काफड़ 78	क्षेत्रफल 3237.07 वर्गमीटर	उत्तर में ख.नं. 701/78 दक्षिण में ख.नं. 79 पूर्व में कटनी रास्ता पश्चिम में ख.नं. 701/78	
3.	प.सं. LSGCU90A/2025-26/104483 श्री रविन्द्र पवार पुत्र श्री नरेंद्र पवार, जाति माली, निवासी वेनार, तहसील व जिला नागौर, श्रीमती निरुद्धा साखला पत्नी श्री अश्विनी साखला, जाति माली, निवासी ताउसर, नागौर हल निवासी घोसाहल बेगम बाजार, देहराबाद	90-ए आवासीय	नागौर 89	क्षेत्रफल 412.48 वर्गमीटर प्लॉट नं. 46 व 47	उत्तर में रास्ता 30 फीट दक्षिण में प्लॉट नं. 48 पूर्व में इसी खसरे की शेष जमीन पश्चिम में रास्ता 30 फीट	
4.	प.सं. LSGCU90A/2025-26/104565 श्री हनुमानप्रसाद पुत्र श्री मिश्रीलाल, जाति ब्राह्मण निवासी खुडीकला, तहसील व जिला नागौर तहसील नागौर	90-ए वाणिज्यिक	नागौर 112/1 451	क्षेत्रफल 40.11 वर्गगज	उत्तर में डामर सड़क दक्षिण में अन्य की जागगा पूर्व में प्लॉट नं. 4 का गेप भाग स्वयं की पश्चिम में प्लॉट नं. 03	
5.	प.सं. LSGCU90A/2025-26/104486 श्री जावेद पुत्र अनवर अली, जाति मुसलमान गौरी, निवासी नागौर, तहसील व जिला नागौर	90-ए आवासीय	नागौर 89	क्षेत्रफल 154.33 वर्गमीटर प्लॉट नं. 39	उत्तर में प्लॉट नं. 40 दक्षिण में प्लॉट नं. 38 पूर्व में बालवा जाने का कच्चा रास्ता पश्चिम में प्लॉट नं. 46	
6.	प.सं. LSGCU90A/2025-26/104644 श्री राजूमल सोनी पुत्र श्री गोपालराम सोनी, जाति सोनी, निवासी दुदावल, तहसील नोखा, जिला बीकानेर	90-ए आवासीय	नकाशा 10	क्षेत्रफल 371.60 वर्गमीटर	उत्तर में इसी खसरे की शेष जमीन दक्षिण में बीकानेर डीडवाना बाईपास रोड पूर्व में इसी खसरे की शेष जमीन पश्चिम में समतलरा साखला का प्लॉट	
7.	प.सं. LSGCU90A/2025-26/104648 श्री रंजीत रेखा पुत्री श्री हंसाज, जाति माली, निवासी काकवाडा, नागौर, तहसील व जिला नागौर	90-ए आवासीय	इन्द्रास 348	क्षेत्रफल 1.4245 हेक्टेयर	उत्तर में खसरा नं. 346, दक्षिण में अन्य खसरा पूर्व में अन्य खसरा पश्चिम में खसरा नं. 1007/564	
8.	प.सं. LSGCU90A/2025-26/104616 श्री परशुराम पुत्र गंगाराम व श्री मंगलराम पुत्र श्री गंगाराम, निवासीगुण अतुसर, तहसील व जिला नागौर	90-ए फर्म हाउस	अतुसर 1474	क्षेत्रफल 9874 वर्गमीटर	उत्तर में अन्य खसरा व ओग सड़क दक्षिण में खसरा नं. 1478 व ख.नं. 1477 व ख.नं. 1479, पूर्व में खसरा नं. 1476 पश्चिम में खसरा नं. 1472	

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए-क और राजस्थान अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन एतद्वारा प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिनियमित अधिकारों के निर्वाह पर कोई आक्षेप है वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर -भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधिकारक्षेत्र के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आ प्रस्तुत कर सकेंगे। उपर्युक्त नियत समय के भीतर -भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तबनुसार मामले का निपटारा किया जाएगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक को जारी की गई।

अधुबक, नगर परिषद, नागौर
DNA-3525

medicines, oxygen, ambulances, and medical personnel. He also emphasised the officials concerned to ensure uninterrupted water, electricity, and basic service delivery.

The CM also reviewed internal security and disaster preparedness across all districts. Reviewing the drill and black-out exercise conducted on Wednesday, he called for effective security at strategically important locations. He ordered the cancellation of police personnel's leaves and instructed them to remain stationed at their respective headquarters. He also told ADG Range officers and nodal secretaries to stay in constant touch with district officials to ensure the implementa-

tion Sindoor, targeted nine ter-

mantled terrorist hideouts in Pakistan and delivered a strong blow to terrorism. "The Congress and the entire nation welcome this action. We stand firmly with the Indian Army and the Government of India," Gehlot said.

am on Wednesday under Opera-

tion Sindoor, targeted nine ter-

orders," said Khajuwala block education officer Badri Ram.

Operation Sindoor was a small step. There should

Civic defence drills bring silence, bunkers from 1971

Mukesh Mathrani

letters@hindustantimes.com

BARMER: Over 50 years have passed since the 1971 India-Pakistan war but its memories remain fresh in the residents along border villages of Rajasthan. With the states conducting civic defence drills like during the previous war, many citizens in border villages near Barmer remember building bunkers and going into hiding when the war sirens were previously sounded.

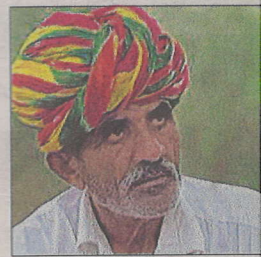
"During the 1971 India-Pakistan war, we built bunkers and supported the army. We used to go on reconnaissance missions and inform the army of any movements on the Pakistani side. If a war breaks out today, Pakistan will not last more than four days," the residents said.

"Back then, Pakistan dropped 16 bombs, but none exploded. It was all due to the blessings of Goddess Hinglaj. The army had

instructed that a long siren meant we had to take cover, while a short siren meant no immediate danger. If the army needs us again, we are ready to help in every possible way," they added.

Shanti Devi, a resident of the remote Gadra Road village, recalled how villagers tried to survive during the 1971 war. "We cooked dinner during the day. At night, not a single fire was lit. Windows were sealed with mud so that not even the tiniest light could escape. Even the flame from the cooking fire was covered."

Prag Singh Sodha (82) from Ramsar said: "Even during the 1971 war, the army conducted mock drills. We were taught when to hide and when it was safe to come out. We understood the sirens." "We made bunkers in our fields — these were pits where we would hide whenever a long siren sounded. The siren



Ransingh Dedusar

usually meant Pakistani planes were approaching, so we knew an attack was coming. We already dug hiding pits near our homes. As soon as the siren went off, we would rush into them and stay hidden for hours. Only when the army sounded short siren would we feel relieved and come out," he said.

Among the residents is Chhota Singh (65) from Harsani village who fought during the 1971 war. He said that the villagers along the border had supported



CM Bhajan Lal Sharma at a high-level meeting with senior police officials at the chief minister's office on Wednesday. HT PHOTO

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District-Nagaur 341001, email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "मैसर्स जे एस इन्क्यू सीमेंट लिमिटेड, 3सी। चूना पत्थर ब्लॉक, खान पट्टा क्षेत्र 300.7284 हेक्टेयर है और प्रस्तावित चूना पत्थर उत्पादन क्षमता- 1.45 मिलियन टीपीए, ओबी/आईबी/अपशिष्ट @ 0.52 मिलियन टीपीए, शीर्ष मृदा @ 0.07 मिलियन टीपीए, कुल उत्खनन 2.04 मिलियन टीपीए के साथ क्रशर क्षमता 1600 टीपीए की वॉबलर के साथ स्थापना, निक्ट गांव हरिमा, भड़ाना एवं डेह एवं तहसील- नागौर एवं डेह, जिला-नागौर (राजस्थान) की पर्यावरण स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया है।
- और चूंकि मैसर्स जे एस इन्क्यू सीमेंट लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
- और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
- और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इंगरी, जयपुर।
2 पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3 क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जयपुर। 4. जिला कलेक्टर, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर। 6. CEO जिला परिषद नागौर। 7. उपखण्ड अधिकारी, नागौर। 8. तहसीलदार नागौर। 9. तहसीलदार डेह। 10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 11. जिला उद्योग केन्द्र नागौर। 12. विकास अधिकारी पंचायत समिति, नागौर। 13 ग्राम पंचायत, हरिमा। 14. ग्राम पंचायत, भड़ाना। 15 ग्राम पंचायत डेह। 16. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिंदास सं. 02. पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला नागौर।
- उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 12/06/2025 को प्रातः 10:00 बजे स्थान-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जिंदास सं. 02, पंचायत समिति नागौर, तहसील एवं जिला: नागौर में आयोजित की जायेगी।
अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से पतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

HT Classifieds

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD Imran Khan S/O Mumtaz Khan Residence Ward No. 19 Nardiyan Mohalla Rajaggarh Churu. I Nereby Declare That My Correct Name Is My All Document Is Mohammad Imran Khan But In My Passport It Is Wrongly Written As Imran Khan So I Want To Correct Is As Mohammad Imran Khan In My Passport

I, SHT BHOLA NATH KHANRA is legal father of JC 769576P, Rank - SUB, Trade: MTECELE, Name- Bijan Khanra presently residing at Vill kumrul, PO. Kumrul, Dist. HOOGHLY, STATE. WEST BENGAL, PIN -712410. I have changed my name SHT BHOLA NATH KHANRA to BHOLANATH KHANRA vide affidavit no BZ608326 before Distt court jodhpur Raj.

I, RANI Devi Wife of Army No 15582716X Hav Sanjeev Singh of 109 Rapid (S) Engr Regt C/o 56 APO- 914109 have change of my name from Rani Devi to Rani in my husband's service record. Vide Affidavit dt 07.05.25 before Kota Court (Raj)

I, PINGALE SUDAM RAMCHANDRA Father of Army no 15584540W Hav PINGALE YOGESH SUDAM OF 109 Rapid(S) Engr Regiment c/o 56 APO have to change My DOB from 20/05/ 1959 to 01/01/1958 in my Son's service record.

CHANGE OF NAME

I, 17000786W Rank- NK, Name -Vanza Dineshkumar Jeshabhai, Permanent Address at Village & Post- Moti fafni, Teh-Kodinar, Dist-gir Somnath, State Gujarat, Pin 362720. I have changed my son Name from RUDRA to RUDRA DINESHKUMAR VANZA his date of birth. 09/07/2022 vide affidavit no BX 139912 dt 31/03/2025 before Distt court jodhpur Raj.

I, ARMY no 15210614M Ex Hav Raj Kumar Sharma S/O Radhya Shyam resident of yadavo ki dhani ke pass village & post Baswa tehsil Baswa district Dausa that have changed my father name From RADHYA SHYAM which wrongly entered in my service record To RADHYA SHYAM SHARMA vide affidavit dated 2 may 2025 before district notary Jaipur

I, ANJANABAI SUPAN Mother of Army no 15584540W Hav PINGALE YOGESH SUDAM OF 109 Rapid(S) Engr Regiment c/o 56 APO have to change My Name from ANJANABAI SUPAN To ANJANABAI SUDAM PINGALE and DOB from 28/06/1964 to 01/01/1960 in my Son's service record.

{ THREATENING OFF

SC upholds term for

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

JAIPUR: The Supreme Court Wednesday upheld BJP MP Kanwarlal Meena's three-year jail term for threatening an official at gunpoint and asked to surrender in two weeks.

While hearing a special leave petition by Meena against Rajasthan high court order upholding a trial court order convicting Meena, a three-judge bench of justice Vikram Nand Lal Saxena, justice Sanjay Karol and justice Sandeep Mehta upheld Rajasthan high court order.

Meena has been accused of putting a gun to the head of SDM Ramniwas Mehta, threatening to kill him, on January 3, 2005. Meena along with villagers reached the SDM's office to stage a dharna demanding a recount in the Sarpanch election in Khatak. He also threatened IAS prisoner Preetam B Yashwanth